शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 12 | अंक : 355 | गुवाहाटी | शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

सीसीटीवी फुटेज में संसद भवन के करीब दिखे प्रदर्शनकारी, सुरक्षा पर सवाल पेज 2
असम में बाढ़ से अभी भी सात जिले प्रभावित, तीन और लोगों की मौत पेज 3
बेअदबी कानून बनाने में पंजाब सरकार ने दिखाई गैर-संजीदगी : जत्थेदार गडगज पेज 5
रैना बोले, अनुशासन, कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से अच्छा फील्डर बना पेज 7

असम में बाढ़ के हालात चिंताजनक

अरुणाचल और नगालैंड में भारी बारिश की संभावना

गुवाहाटी। असम के कई जलमग्न इलाकों में जलस्तर के कम होने के बावजूद गुरुवार को भी बाढ़ की चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में अब तक बाढ़ जनित घटनाओं में 78 लोगों की मौत हुई और तीन लाख से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले तीन दिनों में राज्य और पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश एवं नगालैंड के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे इन दोनों राज्यों की सीमा से लगे जिलों के लिए चिंता बढ़ गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के एक अधिकारी ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित ऊपरी असम के अधिकतर जिलों में बारिश नहीं हुई। इसलिए, डूबे हुए जलमग्न गांवों में पानी घट रहा है, जिससे ग्रामीणों को कुछ राहत मिली। प्राधिकरण की ओर से बुधवार रात जारी बाढ़ संबंधित दैनिक बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में बाढ़ जनित घटनाओं में शिवसागर जिले -शेष पृष्ठ दो पर

राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र से पैकेज की मांग की : सीएम

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गुरुवार को कहा कि राज्य ने अभूतपूर्व बाढ़ से तबाह हुए लोगों की राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र से सहायता पैकेज की मांग की है। राज्य सरकार ने अपनी मांग अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के समक्ष रखी, जिसने बुधवार को ऊपरी असम के बाढ़ प्रभावित जिलों का अपना चार दिवसीय दौरा पूरा किया। इस साल की बाढ़ अभूतपूर्व पैमाने पर आई है, जिससे तबाही का एक निशान छूट गया है, जिसे हमारी डबल इंजन सरकार हमारे लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए कदम उठाएगी, शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऊपरी असम में आई बाढ़ को *असामान्य, उच्च तीव्रता वाली, तीव्र गति से शुरू होने वाली घटना* के रूप में मान्यता देने की मांग रखी है, जिसमें क्षति आकलन और सहायता के लिए लचीले मानदंड शामिल हों। शर्मा ने कहा कि इसने शिवसागर, चराईदेउ, जोरहाट और गोलाघाट के लिए राहत, आवास, बुनियादी ढांचे और आजीविका बहाली को कवर करने वाले *समर्पित केंद्रीय सहायता पैकेज* की मांग की। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि राज्य ने इस पैकेज के तहत केंद्र से कितनी धनराशि मांगी है। शर्मा ने कहा कि असम ने पूर्वोत्तर आपदा जोखिम न्यूनीकरण तंत्र की स्थापना की भी मांग की है ताकि असम और सात पड़ोसी राज्यों को शामिल करते हुए आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में क्षेत्रीय समन्वय को मजबूत किया जा सके। असम में गुरुवार को भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी रही, हालांकि राज्य के अधिकांश हिस्सों से पानी कम हो गया था। मृतकों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है और तीन लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए आश्वासनों के अनुसार, राहत, बहाली और -शेष पृष्ठ दो पर

बाढ़ पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़ी है प्रदेश भाजपा

गुवाहाटी (हि.स.)। असम में हालिया विनाशकारी बाढ़ के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दावा किया है कि पार्टी के कार्यकर्ता राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों में पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटे हुए हैं। भाजपा प्रदेश मुख्यालय अटल बिहारी वाजपेयी भवन से जारी बयान में भाजपा असम प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट अशीष भराली ने कहा कि पार्टी बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार के साथ संवेदना, सेवा और समर्पण की भावना से खड़ी है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने, राहत सामग्री पहुंचाने तथा अब पुनर्वास और क्षतिग्रस्त घरों व गांवों के पुनर्निर्माण तक भाजपा कार्यकर्ता लगातार सक्रिय हैं। भारतीय जनता युवा -शेष पृष्ठ दो पर

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति : मुख्यमंत्री ने एपीडीसीएल कर्मियों की सराहना की

गुवाहाटी (हि.स.)। असम में आई प्रलयंकारी बाढ़ के चलते घर-बार, खेती-पथार, इंसानों के साथ ही मूलभूत संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचा है। आधुनिक युग में विद्युत का महत्व इंसानी जीवन में काफी बढ़ गया है। बाढ़ ने खासकर उपरी असम के शिवसागर, चराईदेउ, जोरहाट एवं गोलाघाट जिलों में काफी प्रभाव डाला है। जिसके चलते विद्युत की आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गयी है। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए जहां सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर मदद पहुंचाने का कार्य जारी है, वहीं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बहाल करने के लिए भी संबंधित विभाग चौबीसों घंटे काम कर रहा है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने विद्युत आपूर्ति बहाल करने के कार्य में जुटे एपीडीसीएल के कर्मचारियों के कदम की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर गुरुवार को एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि इस कठिन समय में आम जनता के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बाढ़ प्रभावित कई क्षेत्रों में -शेष पृष्ठ दो पर

door graph Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

गोमूत्र विशेषज्ञ टिप्पणी पर बवाल शिक्षाविदों ने प्रियंका को घेरा

नई दिल्ली (हि.स.)। देश के कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को संबोधित एक खुला पत्र जारी कर संसद में सार्वजनिक विमर्श की गरिमा बनाए रखने की अपील की है। पत्र में कहा गया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि सार्वजनिक जीवन में असहमति और आलोचना किस स्तर की भाषा तथा तर्क के साथ व्यक्त की जाती है। पत्र में विशेष रूप से आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटि पर की गई कथित टिप्पणी पर चिंता जताई गई। हस्ताक्षरकर्ताओं का कहना है कि किसी वैज्ञानिक या शिक्षाविद के विचारों से -शेष पृष्ठ दो पर

भोजशाला विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम आदेश

परिसर के पास होगी शुक्रवार की नमाज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह धार में विवादित भोजशाला-कमल मौला परिसर के पास मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए शुक्रवार की नमाज अदा करने की उचित व्यवस्था करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जरूरत हो, तो दोनों पक्षों की आपसी सहमति से पास की कोई दूसरी जगह भी चुनी जा सकती है। यह आदेश तब आया जब मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा चुनी गई वैकल्पिक जगह विवादित परिसर से बहुत दूर थी और सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों के मुताबिक नहीं थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस महीने की शुरुआत में दिए गए अपने अंतरिम आदेश को स्पष्ट किया और कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच खसरा नंबर 596 पर शुक्रवार की नमाज अदा करने की अनुमति होगी; यह जगह विवादित स्थल से सटी हुई दरगाह की जमीन बताई गई थी। बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह उस जगह पर नमाज की सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम करे। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर चुनी गई जमीन उपयुक्त नहीं पाई जाती है, तो राज्य सरकार और मुस्लिम समुदाय आपसी सहमति -शेष पृष्ठ दो पर

शेख हसीना को सरेंडर करने से पहले ही गिरफ्तार किया जाएगा : कानून मंत्री

ढाका। बांग्लादेश के कानून मंत्री एम असदुज्जमां ने गुरुवार को कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से लौटने पर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किए जाने की संभावना है, इससे पहले कि उन्हें सीधे अदालत में सरेंडर करने का मौका मिले। उनका बयान हसीना की ओर से एक समाचार एजेंसी को दी गई उस जानकारी के बाद आया है कि जान को खतरा होने के बावजूद वह दिसंबर तक अपने देश लौटने के लिए दृढ़ हैं। हसीना ने दावा किया कि हो सकता है कि मेरी हत्या कर दी जाए। हो सकता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। हो सकता है कि मुझे जेल भेज दिया जाए। हसीना ने आगे कहा -शेष पृष्ठ दो पर

सुप्रभात

व्यसनी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता।

- आचार्य चाणक्य

न्यूज गैलरी

जीएमसीएच में छत की सिलिंग गिरने से चार घायल

गुवाहाटी (हि.स.)। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में गुरुवार को छत की सिलिंग का एक हिस्सा गिर गया, जिससे चार मरीज घायल हो गए। जिसके चलते मरीजों व हॉस्पिटल स्टाफ के बीच अफरा-तफरी मच गई। शुरुआती -शेष पृष्ठ दो पर

तमिलनाडु : घर में आग बुझाते समय फटा सिलिंडर दस बुरी तरह घायल

तंजावुर। तमिलनाडु के तंजावुर में गुरुवार को एक घर में लगी आग को बुझाने की कोशिश के दौरान रसोई गैस सिलेंडर फटने से किशोरी समेत 10 लोग बुरी तरह घायल हो गए। सात की हालत गंभीर है। यह घटना तड़के करीब दो बजे एक किसान मुरुगायन के घर में हुई। पड़ोसियों ने आग की लपटें देखीं। वे परिवार को बाहर निकालने और आग बुझाने के लिए दौड़े। जब कई लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी -शेष पृष्ठ दो पर

पीएम मोदी ने की हाई-लेवल मीटिंग

मिडल ईस्ट संकट पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर मंथन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की एक हाई-लेवल बैठक हुई, जिसमें देश के प्रमुख मंत्री और सुरक्षा अधिकारी शामिल रहे। सूत्रों के अनुसार, बैठक में पश्चिम एशिया के बदलते हालात और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ईंधन की सप्लाई पर इसके असर की समीक्षा की गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू और जेपी नड्डा शामिल हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सरकार और सुरक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ईरान और -शेष पृष्ठ दो पर

नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शन मामले में आपराधियों को छोड़ किसी पर नहीं होगी कार्रवाई

नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली में नीट परीक्षा लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने गुरुवार को इसकी आधिकारिक जानकारी दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत केवल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को ही संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि 29 जुलाई तक नीट (यूजी) परीक्षा में कथित अनियमितताओं से संबंधित प्रदर्शनों के सिलसिले -शेष पृष्ठ दो पर

रास में पेपर लीक रोकथाम विधेयक पर सत्तापक्ष व विपक्ष के बीच तीखी बहस

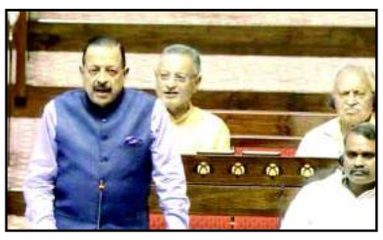

नई दिल्ली (हि.स.)। राज्यसभा में गुरुवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026 पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से सवाल किया कि पेपर लीक रोकने के लिए यह विधेयक पहले क्यों नहीं लाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के बजाय राजनीति करने में व्यस्त रही। खड़गे ने कहा कि आप यह विधेयक सुधारों के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए -शेष पृष्ठ दो पर

जयपुर में जुटेंगे राष्ट्रमंडल देशों के न्यायाधीश

चीफ जस्टिस सूर्यकांत करेंगे तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन

जयपुर (हि.स.)। राजधानी में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें मेडिएशन, रूल ऑफ लॉ तथा न्याय तक प्रभावी एवं समावेशी पहुंच से जुड़े समकालीन वैश्विक विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत 31 जुलाई को सायं 6 बजे सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (आरएसएलएसए), कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन (सीएलए), सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) तथा मेडिएटर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में यह सम्मेलन जयपुर स्थित होटल द ललित में होगा। इस सम्मेलन में राष्ट्रमण्डल देशों के न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी, वरिष्ठ -शेष पृष्ठ दो पर

नेपाल में भारी बवाल : हिंसा के बाद भारत सीमा पर हाई अलर्ट, दो जिलों में कर्फ्यू

काठमांडू। नेपाल के दक्षिणी हिस्से में सांप्रदायिक तनाव लगातार भयावह रूप लेता जा रहा है। 26 जुलाई को सुनसरी जिले के कप्तानगंज में दो समुदायों के बीच भड़की हिंसक झड़प और एक युवक की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। नतीजा, नेपाल के दक्षिणी हिस्से यानी भारत के बिहार राज्य से लगी सीमा वाले क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा के बाद तनाव और बढ़ गया है। ऐसे में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए नेपाल के सुनसरी और सिराहा जिलों के कई हिस्सों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। स्थिति बिगड़ने के खतरे को देखते हुए सिराहा जिला प्रशासन ने गुरुवार दोपहर 2 बजे से अगले आदेश तक कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। यह दायरा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग के कसाहा खोला से लेकर चोहरवा चौक तक और उत्तर-दक्षिण के कई महत्वपूर्ण चौराहों तक फैला हुआ है। इसके अलावा सुनसरी जिले के कई इलाकों जैसे कि इनरुवा, दुहाबी, भोक्राहा, और देवानगंज आदि में पहले से लगा कर्फ्यू गुरुवार को भी जारी रहा। बता दें कि यह घटना 26 जुलाई को सुनसरी जिले के देवांगगंज ग्रामीण पालिका के कप्तानगंज इलाके में हुई थी। सावन के पवित्र महीने में -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
94350-14771

सीसीटीवी फुटेज में संसद भवन के करीब दिखे प्रदर्शनकारी, सुरक्षा पर सवाल

नई दिल्ली (हि.स.)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के दौरान संसद भवन के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं। संसद परिसर के आसपास लगे पांच सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद भवन के काफी करीब तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, मौके पर पहले से दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के जवान तैनात थे और स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला तथा कई लोगों को हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक उस दिन नई दिल्ली जिले के एनडीएमसी क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्र के निकट पहुंच गए। फुटेज में कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की, नारेबाजी और तनावपूर्ण स्थिति भी दिखाई दे रही है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार प्रदर्शनकारी रेल भवन के पास बने सेल्फी पॉइंट तक पहुंच गए। वीडियो में सेल्फी पॉइंट का दाहिना पिलर साफ दिखाई देता है। वहीं बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते और प्रदर्शन करते नजर आते हैं। इस दौरान पुलिसकर्मी उन्हें आगे बढ़ने से रोकते दिखाई देते हैं, जिससे कई बार आमना-सामना और झड़प जैसी स्थिति बन गई। फुटेज में केंद्रीय सचिवालय के साइन बोर्ड के पीछे संसद भवन स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि दूसरी ओर पार्लियामेंट एनेक्सी की इमारत भी नजर आती है। वीडियो में आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवान सुरक्षा घेरे में तैनात दिखाई दे रहे हैं। हालात तनावपूर्ण होने पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और भीड़ को वहां से हटाया। फुटेज सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। संसद मार्च की पूर्व सूचना होने और धारा 163 लागू रहने के बावजूद प्रदर्शनकारी संसद भवन के निकट तक कैसे पहुंच गए? शुरुआती स्तर पर उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग और सुरक्षा घेरा कितना प्रभावी रहा, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की समीक्षा कर रही हैं। हालांकि, दिल्ली पुलिस की ओर से मौके पर स्थिति नियंत्रित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की गई और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया गया। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण किया जा रहा है।

अरुणाचल प्रदेश : भारत-म्यांमार बॉर्डर हाट व्यापार के लिए फिर से खुला

इटानगर (हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश के व्यापार और वाणिज्य मंत्री, न्याटो डुकाम ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में नामपोंग के पास पांसो पास इलाके में भारत-म्यांमार बॉर्डर हाट को फिर से शुरू करने करने के लिए इसका आधिकारिक उद्घाटन किया। इसका मकसद सीमा-पार व्यापार, आर्थिक गतिविधियों और क्षेत्रीय संबंधों को फिर से मजबूत करना है। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए, मंत्री डुकाम ने इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में व्यापार और वाणिज्य की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय समुदायों, व्यापारियों और प्रशासनिक निकायों सहित सभी संबंधित लोगों से सक्रिय रूप से जुड़ने और व्यापार को रोजमर्रा की जिंदगी का एक जीवंत और टिकाऊ हिस्सा बनाने का आह्वान किया। पांगसाऊ दर्रे के ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए नामपोंग में एक नए लैंड पोर्ट की योजना का भी जिक्र किया। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों, नागरिक प्रशासकों, सुरक्षा अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें नामपोंग निर्वाचन क्षेत्र के विधायक लैसम सिमाई, व्यापार और वाणिज्य मंत्री के सलाहकार डॉ. महेश चाई, अरुणाचल प्रदेश सरकार के व्यापार और वाणिज्य सचिव बुल्लो मामू और अन्य शामिल थे।

बीटीसी प्रमुख ने *चीफ रिलिफ* फंड किया लांच

कोकराझाड़ (हिंस)। बोड़ोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) बजट सत्र 2026-27 के समापन के बाद आज कोकराझाड़ स्थित बीटीसी भवन में बीटीसी के मुख्य कार्यकारी पार्षद हग्रामा महिलारी ने *चीफ रिलिफ फंड* का शुभारंभ किया। इस राहत कोष का उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को राहत प्रदान करना, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना, शिक्षा में सहयोग देना, आपदा राहत कार्यों को समर्थन देना तथा बीटीसी क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना है। यह सहायता धर्म, जाति, समुदाय, भाषा या किसी भी भेदभाव से परे प्रदान की जाएगी। कोष में योगदान देने के इच्छुक लोग डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.चीफरिलीफफंडडॉटइन के माध्यम से दान कर सकते हैं। सहायता या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 9435027116 पर संपर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर उद्यमी मोहम्मद इलियास अंसारी ने 5 लाख रुपए तथा ईएम लखी दास ने 1 लाख रुपए का चेक बीटीसी प्रमुख हग्रामा महिलारी को राहत कोष के लिए सौंपा। महिलारी ने आम जनता, विभिन्न संगठनों और शुभचिंतकों से इस फंड में उदारतापूर्वक योगदान देने की अपील की, ताकि जरूरतमंद लोगों के कल्याण और सहायता के लिए इस पहल को और मजबूत बनाया जा सके।

पाकिस्तान: पुलिस चेकपोस्ट पर हमले में डीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों की मौत

हंगू (हि.स.)। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हंगू जिले में खजाना बांदा पुलिस चेकपोस्ट पर मंगलवार देर रात आतंकवादियों ने बड़ा हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार, हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन में एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) दियार खान समेत 11 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। जबकि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 15 हमलावरों को मार गिराया गया। पाकिस्तानी उर्दू टीवी चैनल दुनिया न्यूज के मुताबिक जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) मुजाहिद हुसैन ने बताया कि मुठभेड़ में 28 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हमलावरों ने पुलिस की तीन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और एक वाहन अपने साथ ले गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। फिलहाल, किसी भी संगठन ने अभी तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत हाल के महीनों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकी हमलों से प्रभावित रहा है। यह हमला टैंक जिले में कुछ दिन पहले हुए एक अन्य हमले के बाद हुआ है, जहाँ विस्फोटकों से लदे वाहन के जरिए सुरक्षा चेकपोस्ट को निशाना बनाया गया था। उस हमले में सैनिकों, पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों समेत 15 लोगों की मौत हुई थी, जबकि सेना ने 12 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया था। हमले के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़ी है। पाकिस्तान लंबे समय से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों के लिए अफगानिस्तान से संचालित चरमपंथी समूहों को जिम्मेदार ठहराता रहा है, जबकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आरोपों से लगातार इनकार करती रही है।

ई-20 से इंजन खराब होने का कोई प्रमाण नहीं, नितिन गडकरी ने गिनाए एथनॉल मिक्स्ड फ्यूल के फायदे

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई-20) के इस्तेमाल से वाहनों की ईंधन दक्षता (माइलेज) में दो से छह प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। यह कमी वाहन की श्रेणी और उसकी उम्र पर निर्भर करेगी यानी वह कितना पुराना है। हालांकि, गडकरी ने स्पष्ट किया कि अब तक किए गए वैज्ञानिक परीक्षणों में ई-20 के कारण इंजन खराब होने या किसी गंभीर तकनीकी खराबी का कोई प्रमाण नहीं मिला है। गडकरी ने एक लिखित उत्तर में बताया कि ई-20 पेट्रोल से वाहनों में बेहतर एक्सेलेरेशन, स्मूथ ड्राइविंग अनुभव और ई-10 पेट्रोल की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत कम कार्बन उत्सर्जन होता है। इससे पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। नितिन गडकरी ने बताया कि ई-20 के प्रभाव का अध्ययन आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया (एआरएआई), सोसाइटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) और इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसीएल) ने संयुक्त रूप से किया। इस अध्ययन में बीएस-3, बीएस-4 और बीएस-6 मानकों वाले दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर लैब और सड़क दोनों स्तरों पर परीक्षण किए गए। सभी परीक्षण वाहन निर्माताओं के सहयोग से निर्धारित मानकों के अनुसार किए गए। मंत्री ने कहा कि ई-20 पेट्रोल को लेकर विपक्ष और कुछ उपभोक्ता संगठनों ने पुराने वाहनों की अनुकूलता, कम माइलेज और संभावित रखरखाव लागत को लेकर सवाल उठाए हैं। सरकार का कहना है कि ई-20 को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है और इसके पीछे व्यापक वैज्ञानिक परीक्षण तथा तकनीकी संस्थानों की सलाह शामिल रही है। गडकरी के अनुसार, 2006 में ई-5 लागू किया गया और बाद के वर्षों में इसे धीरे-धीरे बढ़ाया गया। उन्होंने बताया कि पिछले ढाई वर्षों से ई-19 और ई-20 पेट्रोल का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। मंत्री ने दावा किया कि देश में 20 करोड़ से अधिक दोपहिया और तीन करोड़ से ज्यादा पेट्रोल कारें इन मिश्रित ईंधनों पर चल रही हैं, लेकिन एथनॉल मिश्रण के कारण बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने या वाहन बंद पड़ने की कोई पुष्टि नहीं हुई है।

पृष्ठ एक का शेष

असम में बाढ़ के...

में दो और गोलाघाट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसी के साथ इस साल बाढ़ जनित घटनाओं में मरने वालों की कुल संख्या 78 हो गई है। बुलेटिन में जानकारी दी गई कि इस समय कुल 3,00,031 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें से चराईदेउ में सबसे अधिक 1,37,561 लोग प्रभावित हैं। इसके बाद शिवसागर में 84,600 और जोरहाट में 49,911 लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं। एएसडीएमए ने बताया कि बाढ़ की वजह से विस्थापित 16,500 से अधिक लोगों ने कुल 71 राहत शिविरों में शरण ली है। इनके अलावा, 30 राहत वितरण केंद्र 72,000 से अधिक लोगों की मदद कर रहे हैं। मालूम हो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा से फोन पर बात की और राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। वहीं, मुख्यमंत्री ने बताया कि जलस्तर में कमी आई है लेकिन कई लोग अपने घरों को नहीं लौट पा रहे क्योंकि उनके घर या तो क्षतिग्रस्त हो गए हैं या फिर उनमें कीचड़ और गाद भर गई है। बुलेटिन के मुताबिक 21,523.08 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है और 11,000 से अधिक मवेशी बाढ़ में बह गए हैं जबकि 17,000 अन्य प्रभावित हुए हैं। इस बीच, आईएमडी ने 30 जुलाई से एक अगस्त के बीच असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई है, जिससे असम के तिनसुकिया, धेमाजी और लखीमपुर जिले प्रभावित हो सकते हैं।

राज्य सरकार ने बाढ़ ...

पुनर्वास प्रयासों का जमीनी स्तर पर आकलन करने और समीक्षा करने के लिए आईएमसीटी ने राज्य का दौरा किया। उन्होंने आगे कहा कि समीक्षा के दौरान, टीम को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, कृषि और आजीविका को हुए व्यापक नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, असम ने प्रभावित परिवारों को परेशानी मुक्त सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए केंद्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत दस्तावेजीकरण और पात्रता मानदंडों में छूट की मांग की है। इसके अलावा, उन्होंने केंद्र से सड़कों, पुलों, स्कूलों, स्वास्थ्य, जल और बिजली के बुनियादी ढांचे के लिए जिलावार पुनर्निर्माण योजना और अगले मानसून से पहले पहाड़ी नदियों पर टूटे हुए तटबंधों का त्वरित बहु-एजेंसी मूल्यांकन और सुदृढ़ीकरण करने की भी मांग की। अंत में, राज्य ने आपदा सहायता को आवास, जल, कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ समन्वित करने का अनुरोध किया, साथ ही महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए लक्षित सहायता का भी अनुरोध किया, शर्मा ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि हमें विश्वास है कि टीम जमीनी हकीकतों और हमारे हितों को ध्यान में रखेगी और उसी के अनुसार केंद्र सरकार से संवाद करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने बुधवार को असम के मुख्यमंत्री को फोन करके बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि बाढ़ का पानी कम हो गया है, लेकिन कई लोग वापस नहीं लौट पा रहे हैं क्योंकि उनके घर या तो क्षतिग्रस्त हो गए हैं या कीचड़ और गाद से भर गए हैं। शाह ने सात दिनों में दूसरी बार शर्मा को फोन किया और उन्हें राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

बाढ़ पीड़ितों के साथ...

मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ता प्रभावित क्षेत्रों में घरों, आंगनों और सार्वजनिक स्थानों से कीचड़ हटाकर सफाई अभियान चला रहे हैं, ताकि सामान्य जनजीवन जल्द बहाल हो सके। भराली ने बताया कि नाजिरा, सोनारी, महमारा और डिमो विधानसभा क्षेत्रों के विधायक मयूर बरगोहाईं, धर्मेश्वर कोंवर, सूरज दिहिंगिया और सुशांत बरगोहाईं राहत एवं पुनर्वास कार्यों का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं मंत्री बिमल बोरा, अतुल बोरा, अजंता नेउग, रामेश्वर तेली और पवित्र मार्घेरिटा भी प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की है। पार्टी के बयान के अनुसार, बुधवार को भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी भवन से लगभग 16 करोड़ रुपए मूल्य की राहत सामग्री रवाना की, जिसमें 1.80 लाख मेखला-चादर, 1.80 लाख बच्चों की टी-शर्ट तथा 1.50 लाख मच्छरदानियां शामिल हैं। इसके अलावा, असम को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड ने शिवसागर और चराईदेउ जिलों के अपने ऋणधारकों को छह महीने तक ईएमआई भुगतान में स्थगन (मोराटोरियम) देने की घोषणा की है। भाजपा ने कहा कि वह बाढ़ प्रभावित प्रत्येक नागरिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और राहत, पुनर्वास तथा सामान्य जनजीवन की बहाली तक अपनी सेवाएं जारी रखेगी।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ...

एहतियाती उपाय के तौर पर अस्थायी रूप से बिजली सप्लाई बंद रखी गई थी। अब जैसे ही पानी सूखना शुरू हुआ, असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) के बिजली योद्धाओं ने दिन-रात एक करके क्षतिग्रस्त खंभे, विद्युत लाइन, ट्रांसफॉर्मर और अन्य नेटवर्क को युद्धकालीन तत्परता के साथ मरम्मत पूरी की है। उन्होंने कहा है कि व्यापक सुरक्षा जांच के बाद बाढ़ प्रभावित लगभग सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति तेजी से सामान्य रूप से बहाल कर दी गई है। हजारों परिवारों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और आवश्यक सेवाओं में फिर से रोशनी लौटाने का यह चुपचाप लेकिन असाधारण जिम्मेदारी निभाने वाले हर बिजली योद्धा को मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद।

गोमूत्र विशेषज्ञ टिप्पणी ...

असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन केवल किसी उपाधि, पद या व्यक्तिगत पहचान के आधार पर उन्हें खारिज करना स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप नहीं है। उनका मानना है कि वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के विचारों का मूल्यांकन तथ्यों, शोध और प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए। पत्र में संविधान के अनुच्छेद 51(क)(ह) का उल्लेख करते हुए कहा गया कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा और सुधार की भावना का विकास करे। ऐसे में सार्वजनिक प्रतिनिधियों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे वैज्ञानिक विषयों पर जिम्मेदारी, संतुलन और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखें। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को ऐसा सम्मानजनक वातावरण मिलना चाहिए, जहां वे बिना किसी व्यक्तिगत हमले या उपहास के अपने विचार रख सकें। यदि किसी वैज्ञानिक मत से असहमति हो, तो उसका उत्तर शोध, प्रमाण और तार्किक बहस के माध्यम से दिया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत टिप्पणियों या राजनीतिक व्यंग्य के जरिए। पत्र में यह भी कहा गया कि जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव-प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे जटिल वैज्ञानिक विषयों को राजनीतिक उपहास का विषय बनाने से समाज सार्थक और सूचित बहस का अवसर खो देता है। ऐसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा और विशेषज्ञों के विचार लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं। वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में असहमति और आलोचना का पूरा स्थान है, लेकिन असहमति को व्यक्तिगत उपहास का रूप देना उचित नहीं माना जा सकता। उन्होंने सार्वजनिक प्रतिनिधियों से जिम्मेदार भाषा, गरिमापूर्ण आचरण और तथ्याधारित संवाद अपनाने का आग्रह किया, ताकि संसद स्वस्थ और रचनात्मक बहस का मंच बनी रहे। पत्र के अंत में आशा व्यक्त की गई कि भविष्य में संसद और सार्वजनिक जीवन में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा तथ्यों, प्रमाणों और पारस्परिक सम्मान के आधार पर होगी। यह खुला पत्र प्रो. जी.डी. यादव, प्रो. पंकज मित्तल सहित अनेक वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के समन्वय से जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को प्रियंका गांधी ने लोकसभा में पेपर लीक रोकने संबंधि विधेयक पर चर्चा के दौरान अपने भाषण में आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटि को कथित तौर पर *गोमूत्र विशेषज्ञ* कहकर संबोधित किया था। इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक दलों और शिक्षाविदों के बीच बड़ा विवाद छिड़ गया।

परिसर के पास होगी ...

से पास की कोई दूसरी जगह चुन सकते हैं। कोर्ट के अनुसार, उसके सामने पेश किए गए साइट प्लान से पता चला कि खसरा नंबर 596 तक जाने के लिए एक अलग रास्ता था और यह जगह उपयुक्त लग रही थी क्योंकि यह विवादित परिसर से सटी हुई थी। यह स्पष्टीकरण मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर एक अर्जी पर आया है। अर्जी में कहा गया था कि अभी जो अंतरिम व्यवस्था लागू है, उसके तहत नमाजियों को भोजशाला परिसर से लगभग एक किलोमीटर दूर शुक्रवार की नमाज अदा करनी पड़ती है। इस हफ्ते की शुरुआत में, मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने जो जमीन तय की है, वह उस जगह से कहीं ज़्यादा दूर है जिसके बारे में कोर्ट ने पास की कोई जगह उपलब्ध कराने का निर्देश देते समय सोचा था। मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि जब मुस्लिम पक्ष ने वैकल्पिक जगह की दूरी पर आपत्ति जताई, तो वे खुद इस मामले की जांच करेंगे। यह विवाद मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला-कमल मौला परिसर से जुड़ा है। इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विवादित जगह पर अभी जो व्यवस्था है, वह अस्थायी रहेगी और यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली लंबित अपीलों के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी, जिसमें भोजशाला को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया गया था।

मिडल ईस्ट संकट पर ...

अमेरिका के बीच कई विवादों के बीच, नाजुक युद्धविराम टूट गया। इसकी शुरुआत पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान हुई, जब तेहरान ने खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कसम खाई। इसके अलावा, होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी विवाद चल रहा था; अमेरिका चाहता था कि यह शिपिंग रूट युद्ध से पहले वाली स्थिति में लौट आए, जबकि ईरान का कहना था कि वह इस अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से गुजरने के लिए टोल वसूलेगा। जल्द ही, इसके कारण ईरान के बुनियादी ढांचे पर अमेरिका और इजराइल ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए और ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में ड्रोन और मिसाइल हमले किए। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और ट्रंप ने भी जोरदार हमलों की धमकी देनी शुरू कर दी। राज्यसभा में, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया। लोकसभा से बुधवार को पारित हुए इस विधेयक का मकसद परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों के खिलाफ कानूनी ढांचे को मजबूत करना है। इसके लिए पेपर लीक के मामलों में सजा बढ़ाना, जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाना और समय पर सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करना शामिल है।

नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शन ...

में दिल्ली पुलिस ने कुल 13 मामले दर्ज किए गए थे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने विज्ञप्ति जारी की है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली के अंतर्गत किसी भी पुलिस प्राधिकरण की ओर से इन प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, यह संरक्षण उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिनका आपराधिक रिकॉर्ड (क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स) है। इसमें कहा गया है कि इन मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के मामलों की समीक्षा होगी तथा रिहाई की प्रक्रिया शीघ्रतापूर्वक पूरी की जाएगी। वहीं, इन प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी तथा मामले को समाप्त माना जाएगा।

रास में पेपर लीक...

लेकर आए हैं। खड़गे ने कहा कि सरकार के अधीन जांच एजेंसियां होने और कई राज्यों में भाजपा की *डबल इंजन* सरकारें होने के बावजूद पेपर लीक की घटनाएं लगातार हो रही हैं। यदि सीबीआई, एनटीए और ईडी जैसी संस्थाएं पूरी तरह स्वतंत्र तरीके से काम करतीं, तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। इससे पहले राज्यसभा में गुरुवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर रखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में चार प्रमुख भर्ती एजेंसियां- संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) और उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए)- परीक्षाएं आयोजित करती हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाने का विचार पहली बार 1992 में सामने आया था, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद कई समितियों ने भी ऐसी एजेंसी बनाने की सिफारिश की, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस लंबे समय से लंबित कार्य को पूरा किया और विपक्ष को इसके लिए उनकी सराहना करनी चाहिए। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने 2024 के कानून के क्रियान्वयन से मिले अनुभवों के आधार पर संशोधन किए हैं। यह सरकार की *अनुभव से सीखने की इच्छा* को दर्शाता है। संशोधित विधेयक में पेपर लीक मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करने का प्रावधान किया गया है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सत्र न्यायालयों को विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत के रूप में नामित करने का अधिकार दिया जाएगा, ताकि आरोपपत्र दाखिल होने के तीन महीने के भीतर रोजाना सुनवाई कर मामलों का निपटारा किया जा सके। विधेयक में दोषियों के लिए सजा भी कड़ी की गई है। सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक या अन्य अनुचित साधनों के दोषी पाए जाने पर पांच से दस वर्ष तक की कैद और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, संगठित गिरोहों के मामलों में न्यूनतम सात वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार विशेष जांच कार्यबल (स्पेशल टास्क फोर्स) भी गठित कर सकेगी। जितेंद्र सिंह ने सदन को बताया कि 2024 का कानून लागू होने के बाद अब तक 52 एफआईआर दर्ज की गई हैं और पेपर लीक से जुड़े मामलों के कारण आत्महत्या की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने देश में पूर्व में हुई पेपर लीक की कई घटनाओं का भी उल्लेख किया जिस पर सदन में विपक्ष की ओर से विरोध और हंगामा देखने को मिला।

शेख हसीना को सरेंडर...

कि मुझे अपनी किस्मत के बारे में पूरी जानकारी है। फिर भी, मैं वापस जाना चाहती हूं, क्योंकि मेरे लोग मुझे बुला रहे हैं। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में उनके और भी साक्षात्कार सामने आए थे, जिनसे पता चला था कि वह अपनी पार्टी के सहयोगियों के साथ इस साल के अंत तक बांग्लादेश लौटने की संभावना पर चर्चा कर रही थीं। ऐसे में असदुज्जमां ने कहा कि 78 वर्षीय हसीना को लौटने का अधिकार है, लेकिन कानून अपना काम करेगा और हम कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ भी नहीं करेंगे। मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि मौत की सजा की दोषी होने और बांग्लादेशी नागरिक होने के बावजूद, अगर वह घर लौटकर कानून का सम्मान करते हुए सरेंडर करना चाहती हैं, तो हो सकता है कि ऐसा करने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। हम उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे जो कानून ने हमें दिया है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ...

अधिवक्ता, मेडिएटर्स, विधि विशेषज्ञ, शिक्षाविद्, नीति-निर्माता तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन में 1 अगस्त को पांच तथा 2 अगस्त को दो उच्चस्तरीय तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन का वैलेडिक्टरी सेशन 2 अगस्त को दोपहर 12:15 बजे होगा, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस विक्रम नाथ, जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एवं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, नालसा करेंगे। समापन अवसर पर जयपुर डिक्लेरेशन ऑन पीस मेडिएशन-2026 को सभी विशिष्ट अतिथियों द्वारा अंगीकृत किया जाएगा। सम्मेलन के विभिन्न तकनीकी सत्रों में कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, एनवायरनमेंटल डिस्प्यूट्स, कम्युनिटी डिस्प्यूट्स, क्रॉस-बॉर्डर डिस्प्यूट्स, आपराधिक मामलों में विक्टिम-सेंट्रिक मीडिएशन, रूल ऑफ लॉ को सुदृढ़ बनाने में मीडिएशन की भूमिका तथा वैश्विक स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञ विचार-विमर्श करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य मीडिएशन को विवादों के शांतिपूर्ण, प्रभावी, त्वरित एवं सहमति-आधारित समाधान के रूप में वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करना तथा न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ, उत्तरदायी एवं जन-केंद्रित बनाना है। सम्मेलन में होने वाले विमर्श एवं निष्कर्ष जयपुर डिक्लेरेशन ऑन पीस मेडिएशन-2026 के माध्यम से मेडिएशन की भावी दिशा एवं नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने बताया कि यह सम्मेलन न केवल भारत बल्कि राष्ट्रमंडल देशों के मध्य न्यायिक सहयोग, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन (एडीआर) तथा शांति-आधारित न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा।

नेपाल में भारी बवाल : हिंसा...

हिंदू श्रद्धालु कोशी बराज से पवित्र जल लेकर कप्तानगंज चौक की ओर जा रहे थे और रास्ते में तेज आवाज में डीजे पर संगीत बजा रहे थे। फिर, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने तेज आवाज में संगीत बजाने पर आपत्ति जताई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में पहले बहस हुई, फिर हाथापाई और अंत में यह एक हिंसक झड़प में बदल गई। बढ़ते तनाव को देखते हुए दोनों तरफ से भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिनके पास लाठी, डंडे, बांस और लोहे की छड़ें जैसे हथियार थे। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस दौरान पुलिस की गोलीबारी से ओम प्रकाश मेहता नाम के एक युवक की मौत हो गई। दूसरी तरफ इस पूरे बवाल को लेकर प्रधानमंत्री बालेन शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) की एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में नेपाल की समग्र सुरक्षा स्थिति और सुनसरी की हिंसा पर चर्चा की गई। सरकार ने देश में सामाजिक सद्भाव, शांति और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए सभी पक्षों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि हिंसा के अन्य इलाकों में फैलने के डर से सिराहा और सुनसरी जिलों के कई प्रमुख इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले में प्रशासन का कहना है कि राजनीतिक दलों, स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था अभी भी चाक-चौबंद है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या नई हिंसा को रोका जा सके।

जीएमसीएच में छत ...

रिपोर्ट के मुताबिक, छत की सिलिंग का एक हिस्सा अचानक टूटकर वार्ड के अंदर इलाज करा रहे मरीजों पर आ गिरा। इस घटना से विभाग में अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद हॉस्पिटल के कर्मचारी प्रभावित लोगों की मदद के लिए दौड़े। घायल मरीजों को हॉस्पिटल प्रशासन ने तुरंत मेडिकल मदद दी। अधिकारियों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। रिपोर्ट्स से पता चला है कि प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट की छत की सिलिंग काफी समय से खराब हालत में थी। आशंका है कि स्ट्रक्चर की ठीक से मरम्मत और देखभाल न होने की वजह से यह हादसा हुआ। इस घटना ने असम के प्रमुख सरकारी हेल्थकेयर संस्थानों में से एक के इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव पर चिंता बढ़ा दी है। सिलिंग गिरने की वजह की आधिकारिक जांच के बारे में और जानकारी का इंतजार है।

तमिलनाडु : घर में आग ...

रसोई गैस सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया। धमाके की चपेट में आकर मुरुगायन, उनकी बेटी अभिनया और आग बुझाने में मदद कर रहे कई पड़ोसी घायल हो गए। कुछ 80 प्रतिशत से अधिक झुलस गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

असम में बाढ़ से अभी भी सात जिले प्रभावित, तीन और लोगों की मौत

गुवाहाटी (हिंस)। असम में अभी भी सात जिले बाढ़े प्रभावित हैं। इस त्रासदी में तीन और लोगों की मौत हो गई। बाढ़ की विभिषिका के बाद अब नए सिरे से जीवन जीने के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई है। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित उपरी असम के चार जिलों शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और गोलाघाट में राहत एवं बचाव कार्य सरकारी एवं निजी स्तर पर जोरशोर से चला रहा है। बावजूद इसके लोग अपने घरों में जा नहीं पा रहे हैं। बाढ़ ने सभी कुछ तबाह कर दिया है। बाढ़ का पानी लगातार घट रहा है, जिसके चलते घरों एवं विद्यालयों में घुटनों तक मिट्टी की गाद भर जाने से लोगों के सामने एक नई समस्या पैदा हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 29 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य की सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। सरकार युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव के लिए सभी तरह के उपाय करने में जुटी हुई है। गोलाघाट में 1 एवं शिवसागर में 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। राज्य में मृतकों की कुल संख्या 78 हो गई है। बाढ़ प्रभावित सात जिलों में चराईदेव, गोलाघाट, शिवसागर, नगांव, बिश्वनाथ, जोरहाट एवं कामरूप (मेट्रो) जिला शामिल हैं। इन जिलों के 21 राजस्व मंडलों के कुल 551 गांवों की 300031 आबादी अभी भी प्रभावित हैं एवं 21523.08 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए वर्तमान में कुल 71 राहत शिविर एवं 30 राहत वितरण केंद्र समेत कुल 101 शिविर क्रियान्वित रखे हैं। राहत शिविरों में 16567 लोग आश्रय लिए हुए हैं। जबकि राहत वितरण केंद्रों पर 72210 गैर-शिविर निवासी राहत प्राप्त कर रहे हैं। राहत एवं बचाव अभियान में एसडीआरएफ, सेना/अर्धसैनिक बल, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, एयर फोर्स, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं (एफ एंड ईएस), सर्कल कार्यालय/स्थानीय प्रशासन, नागरिक सुरक्षा/प्रशिक्षित स्वयंसेवक और अग्निशमन विभाग जुटा हुआ है। राज्य सरकार ने 108 मेडिकल टीमों को तैनात किया। इस दौरान 20 नावें भी राहत कार्य में जुटी रहीं। बाढ़ से बड़े पैमाने पर सड़क, पुल एवं अन्य आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इसकी मरम्मत के लिए सरकार लगातार समीक्षा बैठक कर हालात का जायजा ले रही है। बाढ़ के चलते असम विधानसभा का बजट सत्र पूर्व निर्धारित समय से दो दिन पूर्व 29 जुलाई को ही समाप्त किया गया। विधानसभा का सत्र 31 जुलाई तक निर्धारित था।

असम बाढ़ : जेएसडब्ल्यू स्टील के सज्जन जिंदल ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए पांच करोड़

गुवाहाटी (हिंस)। असम में आई विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए जहां सरकार पूरा जोर लगा रही है, वहीं प्रभावितों की मदद के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से सेलिब्रेटी, कंपनियां, सामाजिक संगठन एवं अन्य संगठन भी अपनी-अपनी तरफ से हाथ बढ़ा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री राहत कोष में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भी लगातार लोग आर्थिक अनुदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में जेएसडब्ल्यू स्टील की ओर से पांच करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराया गया है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर गुरुवार को एक पोस्ट शेयर करते हुए जेएसड्ब्ल्यू स्टील की ओर से आर्थिक अनुदान दिए जाने का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सुबह, जेएसडब्ल्यू स्टील के सज्जन जिंदल की दरियादिली ने मेरा दिल छू लिया। उन्होंने बिना किसी को बताए या कोई सूचना दिए, भयानक बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) में 5 करोड़ ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा है कि हमें इस नेक काम के बारे में तब

पता चला जब हमारी टीम आज फंड के बैंक स्टेटमेंट की समीक्षा कर रही थी। इसके लिए कोई घोषणा या बातचीत नहीं हुई थी, बस यह करुणा का एक शांत काम था। असम के लिए यह गर्व की बात है कि उनकी सम्मानित माताजी, सावित्री जिंदल जी (जो ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन एमेरिटस हैं), हमारे राज्य से ही हैं। असम के लोगों की ओर से, मैं सज्जन जी की विनम्रता और उदारता के लिए उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सीएमआरएफ में मिली हर एक पाई का इस्तेमाल असम की बाढ़ से प्रभावित हमारे लोगों की भलाई के लिए बहुत समझदारी और सावधानी से किया जाएगा।

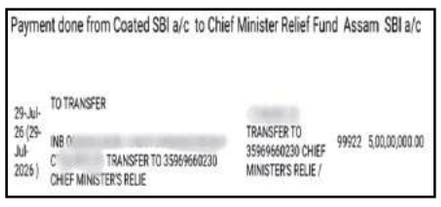

एसएसबी प्रथम वाहिनी के जवानों के लिए 100 दिवसीय योग

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी के सोनापुर स्थित प्रथम वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के कमांडेंट सुनील कौशिक के मार्गदर्शन में *ए* समवाय, रौता एवं *बी* समवाय, भगतपारा में 100 दिवसीय योग कक्षा के तहत आज भी योग अभ्यास किया गया। इस कक्षा का मुख्य उद्देश्य जवानों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, तनाव को कम करना तथा स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम की शुरुआत योग गुरु द्वारा योग के महत्व पर व्याख्यान एवं सामूहिक योगाभ्यास से हुई। इसमें प्राणायाम, सूर्य नमस्कार एवं विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया गया। समवायो के जवानों ने इस कक्षा में शामिल हुए। इस अवसर पर दोनों समवाय प्रभारी ने कहा कि *योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मन को भी शांति प्रदान करता है। 100 दिनों तक निरंतर योग करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।* यह 100 दिवसीय योग कक्षा प्रतिदिन प्रात:काल आयोजित की जाएगी।

असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का राज्यपाल ने किया हवाई सर्वेक्षण राहत शिविरों का लिया जायजा

गुवाहाटी (हिंस)। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुरुवार को शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर नुकसान का जायजा लिया तथा राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। राज्यपाल ने शिवसागर जिले के लक्ष्मी नगर राहत शिविर और शिवसागर हाई स्कूल राहत शिविर का दौरा कर बाढ़ प्रभावित परिवारों से बातचीत की। उन्होंने राहत सामग्री वितरित की और शिविरों में भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। प्रभावित लोगों को आश्वस्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम की बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और राज्य को हरसंभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। राज्यपाल ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि राहत शिविरों में रह रहे बच्चों, महिलाओं, धात्री माताओं, वरिष्ठ नागरिकों और विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रभावित परिवार आवश्यक सहायता से वंचित न रहे। उन्होंने जिला प्रशासन, आपदा राहत दलों, सुरक्षा बलों, स्वास्थ्यकर्मियों, स्वयंसेवकों और स्थानीय समुदायों के प्रयासों की सराहना करते हुए राहत एवं पुनर्वास कार्यों को पूरी संवेदनशीलता और समन्वय के साथ जारी रखने का आह्वान किया।

आईएमसीटी ने असम के बाढ़ प्रभावित चार जिलों का दौरा पूरा किया, केंद्र को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

गुवाहाटी (हिंस)। असम के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट का स्थलीय निरीक्षण पूरा करने के बाद बुधवार को अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) ने अपना दौरा समाप्त कर दिया। दौरे के समापन पर जनता भवन, दिसपुर में मुख्य सचिव डॉ. रवि कोटा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल. स्वीटी चांगसन ने केंद्रीय दल को हालिया बाढ़ की स्थिति, इसके कारणों और राहत एवं पुनर्वास कार्यों के दौरान सामने आई चुनौतियों की जानकारी दी। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एनडीआरएफ, भारतीय सेना, एनएफ रेलवे, एफसीआई, बीएसएनएल, दूरसंचार विभाग तथा अन्य केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एम रामचंद्रुडु के नेतृत्व वाले छह सदस्यीय दल ने 26 जुलाई को चराइदेव, 27 जुलाई को शिवसागर तथा 28 जुलाई को जोरहाट और गोलाघाट का दौरा कर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। राज्य सरकार ने केंद्रीय दल को बताया कि चराइदेव और

शिवसागर जैसे जिले पहले कभी बाढ़ प्रभावित नहीं रहे, लेकिन 19 जुलाई को नगालैंड में सामान्य से 181 प्रतिशत अधिक वर्षा तथा मोकोकचुंग में 493 प्रतिशत, वोक्हा में 108 प्रतिशत और मोन में 45 प्रतिशत अधिक वर्षा के साथ इन जिलों में हुई अत्यधिक स्थानीय वर्षा के कारण अभूतपूर्व बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। सरकार ने बताया कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं तथा स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद से फंसे लोगों का सुरक्षित बचाव किया गया। प्रभावित परिवारों को निर्धारित मानकों के अनुसार राहत सामग्री वितरित की जा रही है तथा चावल, दाल, सरसों का तेल, नमक और मोमबत्ती वाले परिवार राहत किट पड़ोसी जिलों से शिवसागर और चराइदेव भेजे जा रहे हैं। राज्य सरकार ने केंद्रीय दल को बताया कि क्षति का आकलन अभी जारी है और बाढ़ का अंतिम ज्ञापन बाढ़ का मौसम समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। साथ ही, राज्य ने सबसे अधिक प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए एसडीआरएफ सहायता मानकों में कुछ राहत देने का अनुरोध भी किया। केंद्रीय दल ने आश्वासन दिया कि वह अपने निरीक्षण और आकलन की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा, ताकि आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

असम बाढ़ पीड़ितों के लिए बांग्लादेश सहायक उच्चायोग ने दी राहत सामग्री

गुवाहाटी (हिंस)। असम के जोरहाट, शिवसागर और चराइदेव जिलों में हालिया विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए गुवाहाटी स्थित बांग्लादेश सहायक उच्चायोग ने राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, अनेक घर, पशुधन और घरेलू सामान नष्ट हो गए हैं तथा 70 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। मानवीय सहयोग और संवेदना के प्रतीक के रूप में गुवाहाटी में बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त जिक्रूल हसन फहाद ने 50 बाढ़ प्रभावित परिवारों में वितरण के लिए आवश्यक राहत सामग्री प्रतिदिन टाइम के महाप्रबंधक मृण्मय दास को सौंपी। राहत सामग्री में पुरुषों के टी-शर्ट, महिलाओं के वस्त्र, ओआरएस के पैकेट, फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर, स्नान साबुन, बिस्कुट तथा मच्छर भगाने वाली कॉयल शामिल हैं। इन सामग्रियों का उद्देश्य प्रभावित परिवारों की तत्काल स्वास्थ्य, स्वच्छता और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता प्रदान करना है।

सदौ असम गोर्खा छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह सफलतापूर्वक संपन्न

गुवाहाटी (हिंस)। सदौ असम गोर्खा छात्र संघ (एजीएसयू) के नव निर्वाचित 19वें केंद्रीय कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को गुवाहाटी के पांजाबारी स्थित श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र के श्री माधवदेव अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षागृह में उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एजीएसयू के सलाहकार वीरेंद्र चुब्बा ने संगठन के 48 नए केंद्रीय सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाया। शपथ ग्रहण समारोह में अध्यक्ष

नोमल छेत्री, महासचिव सोमराज सोनार सहित सभी नए निर्वाचित पदाधिकारी संगठन और समाज के हित में निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ सेवा देने की प्रतिज्ञा ली। शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक परिचर्चा सभा आयोजित की गई। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में असम के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल और असम के शिक्षा मंत्री डॉ. रणोज पेगू उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर असम गोर्खा सम्मेलन के अध्यक्ष श्रीकृष्ण भुजेल, भारतीय गोर्खा परिसंघ के अध्यक्ष नित्यानंद उपाध्याय, नेपाली साहित्य सभा के अध्यक्ष चिंतामणि शर्मा, सदौ असम गोर्खा छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, गोर्खा समुदाय के विभिन्न जाति-उपजातीय संगठनों के अध्यक्ष और महासचिव, आगसू के बीटीसी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष और महासचिव, विभिन्न जिला समितियों के अध्यक्ष और महासचिव, केंद्रीय और जिला स्तर के पदाधिकारी तथा संगठन के अनेक शुभचिंतक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने नव निर्वाचित नेतृत्व को बधाई दी और आशा व्यक्त किया कि संगठन गोरखा समाज की शिक्षा, एकता, अधिकारों की सुरक्षा, सांस्कृतिक विकास और सर्वांगीण उन्नति के क्षेत्र में और भी मजबूत भूमिका निभाएगा।

गवर्नर ने राज्य विश्वविद्यालयों के लिए चांसलर के नामित लोगों के साथ की बातचीत

गुवाहाटी। असम के गवर्नर और राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर, श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने आज लोक भवन से गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, माजुली यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर (माजुली) और असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (जोरहाट) के विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों और निकायों में चांसलर द्वारा नामित लोगों के साथ वर्चुअल बातचीत की। बैठक के दौरान गवर्नर ने कहा कि चांसलर द्वारा नामित लोगों की नियुक्ति उनकी काबिलियत, ईमानदारी और निष्पक्षता को दर्शाती है। उन्होंने उनसे विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता, जवाबदेही, शैक्षणिक उत्कृष्टता और सुशासन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने का आग्रह किया। यह बताते हुए कि विश्वविद्यालय सीखने, रिसर्च, इनोवेशन और चरित्र निर्माण के केंद्र

हैं, गवर्नर ने नामित लोगों से विश्वविद्यालय प्राधिकरणों की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेने और नीति बनाने तथा संस्थागत निर्णय लेने में रचनात्मक योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने उनसे यह सुनिश्चित करने की अपील की कि सभी निर्णय संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियमों, कानूनों, अध्यादेशों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार लिए जाएं, साथ ही असम सरकार, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और अन्य सक्षम प्राधिकरणों के दिशानिर्देशों का भी पालन किया जाए। श्री आचार्य ने नामित लोगों को सलाह दी कि वे हर बैठक से पहले एजेंडा पेपर्स का अच्छी तरह से अध्ययन करें ताकि किसी भी प्रक्रियात्मक या प्रशासनिक कमी को शुरुआती चरण में ही समझा जा सके और संस्थानों के व्यापक हित में निष्पक्ष, तथ्य-आधारित सुझाव दिए जा सकें। उन्होंने विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और लंबित मामलों को समय पर पूरा करने के महत्व पर भी जोर दिया। गवर्नर ने नामित लोगों को शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय और शासन-संबंधी मुद्दों पर जब भी आवश्यक हो सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया और भरोसा दिलाया कि चांसलर के तौर पर उचित सिफारिशें संबंधित विश्वविद्यालयों तक पहुंचाई जाएंगी। बैठक में गवर्नर के कमिश्नर और सचिव एसएस मीनाक्षी सुंदरम, गवर्नर सचिवालय के सलाहकार प्रो. हरबंश दीक्षित, गवर्नर के हृस्ष्ठ प्रो. बेचन लाल, गवर्नर सचिवालय के संयुक्त सचिव अरिंदम बरुआ और अन्य अधिकारी शामिल हुए।

राज्य के 30 चाय बागानों में घुसा बाढ़ का पानी, 11 बुरी तरह प्रभावित

गुवाहाटी (हिंस)। असम सरकार के मंत्री रामेश्वर तेली ने गुरुवार को कहा कि राज्य में आई बाढ़ की वजह से अब तक लगभग 75 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि, बचाव दल उन इलाकों में तलाशी अभियान चला रहे हैं जो भारी मात्रा में मलबे और कीचड़ के बहाव से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य नगालैंड से बहकर आए भारी मलबे और कीचड़ के नीचे कुछ जगहों पर लोग दबे हो सकते हैं। असम में आई भयावह बाढ़ की स्थिति पर मीडिया से बात करते हुए तेली ने कहा कि राज्य भर में कम से कम 30 चाय बागानों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिनमें से 11 बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि यह जानकारी लेबर कमिश्नर की रिपोर्ट से मिली है।

बीटीसी के लिए 1,588.31 करोड़ का बजट पारित

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर

कोकराझाड़ (हिंस)। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली (बीटीसीएलए) में गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,831.32 लाख यानी करीब 1,588.31 करोड़ का बीटीसी बजट पारित किया गया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है। बीटीसी के मुख्य कार्यकारी पार्षद एवं वित्त विभाग के प्रभारी हग्रामा महिलारी द्वारा प्रस्तुत बजट को सदन ने पारित किया। सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्यों ने इसे जनहितैषी, समावेशी और विकासोन्मुख बजट बताया। सदन को संबोधित करते हुए हग्रामा महिलारी ने कहा कि बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कृषि, सड़क संपर्क और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया। छात्र कल्याण के तहत बोडोफा सुपर-50 कार्यक्रम का विस्तार कर 100 से अधिक विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। इसे अब *यूएन ब्रह्म फ्री यूपीएससी, एपीएससी, नीट एवं जेईई कोचिंग प्रोग्राम* के नाम से संचालित किया जाएगा। एचएसएलसी में एमआईएल विषयों में 100 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को 3 लाख तथा हायर सेकेंडरी के शीर्ष 10 रैंकधारियों को 5 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा विभाग के कार्यकारी सदस्य रबिराम नार्जारी ने बताया कि पिछली यूपीपीएल सरकार के कार्यकाल में नियुक्त किए गए 554 विज्ञान और गणित

शिक्षकों की सेवा वर्तमान बीपीएफ सरकार के तहत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट प्रावधान किया जा चुका है और राशि प्राप्त होते ही शिक्षकों का पारिश्रमिक जारी किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र पर चर्चा के दौरान कार्यकारी सदस्य देरहासात बसुमतारी ने बताया कि बीटीसी में फिलहाल करीब 150 डॉक्टरों और 400 पैरामेडिकल कर्मचारियों की कमी है। उन्होंने कहा कि असम सरकार के साथ चर्चा हो चुकी है और स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद बीटीसी में 150 जीएनएम नर्सों की नियुक्ति की उम्मीद है। वहीं, एमसीएलए धनेश्वर ग्यारी ने 1980 के दशक के अंत में जनजातीय अधिकारों के आंदोलन के दौरान पीटीसीए कार्यकर्ताओं और आब्सू वोलंटिर फोर्स के सदस्यों के योगदान एवं बलिदान का मुद्दा उठाया।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंधों एवं बांधों की मरम्मत के कार्य में तेजी

गुवाहाटी (हिंस)। असम में आई विनाशकारी बाढ़ के चलते उपरी असम की नदियों के तटबंध एवं बांधों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। तटबंधों एवं बांधों के टूटने की वजह से बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसके चलते लाखों लोगों का जीवन-यापन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही प्रशासन जहां राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है, वहीं तटबंध एवं बांधों की अस्थायी तौर पर मरम्मत का कार्य भी तेजी के साथ शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने गुरुवार को बताया कि तटबंधों की मरम्मत के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस पर कामरूप में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

गुवाहाटी (हिंस)। विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस-2026 के अवसर पर गुरुवार को कामरूप जिले के अमीनगांव स्थित एकीकृत जिला आयुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग, असम के अंतर्गत संकल्प : डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कामरूप के जिला आयुक्त देब कुमार मिश्र ने मानव तस्करी और डायन प्रथा (विच-हंटिंग) के संभावित कारणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने मानव तस्करी संभावित और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने, जन-जागरूकता अभियान तेज करने तथा शिक्षा को इस सामाजिक बुराई के खिलाफ प्रभावी माध्यम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सभी विभागों और नागरिकों से मानव तस्करी उन्मूलन तथा कमजोर

वर्गों की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मिशन शक्ति की विभिन्न योजनाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण, संरक्षण एवं कल्याण से जुड़े उद्देश्यों पर प्रस्तुति दी गई। गौहाटी उच्च न्यायालय की अधिवक्ता हरिप्रिया राजबंशी ने मानव तस्करी रोकथाम एवं डायन प्रथा उन्मूलन संबंधी राज्य नीति, कानूनी प्रावधानों, चुनौतियों और संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर विस्तार से जानकारी दी। डीएसपी टिंकुज्योति चौधरी ने मानव तस्करी रोकने के लिए पुलिस की पहल तथा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) की बचाव, जांच, पुनर्वास और विभिन्न एजेंसियों के समन्वय में भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं, सहायक एलएडीसी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है और जरूरतमंदों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर है। कार्यक्रम के दौरान खुली चर्चा भी आयोजित की गई, जिसमें मानव तस्करी और इससे जुड़े सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों को और मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श हुआ। प्रतिभागियों को बताया गया कि बच्चों से संबंधित किसी भी समस्या की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दी जा सकती है। कार्यक्रम में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ गोस्वामी, एडीसी गीताश्री लचित, मुख्य एलएडीसी, प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीडीपीओ तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए नगांव के लोग

नगांव (निसं)। ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए नगांव जिले के लोग आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में नगांव के जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा ने महान गायक भूपेन हजारिका के अमर गीत *मानुहे मानुहर बाबे...* का उल्लेख करते हुए लोगों से बाढ़ पीड़ितों की हरसंभव सहायता करने की अपील की। गुरुवार को नगांव शहर में संगठन *कंठशिल्पी असम* द्वारा आयोजित *सुरीया आह्वान* नामक विशेष बाढ़ राहत संग्रह एवं वितरण अभियान का शुभारंभ करते हुए जिला आयुक्त ने कहा कि आपदा की इस कठिन घड़ी में सभी को एकजुट होकर संकटग्रस्त लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंठशिल्पी असम की यह मानवीय पहल समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश है। कार्यक्रम में नगांव-बटद्रवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रूपक शर्मा भी शामिल हुए और आयोजकों की इस सराहनीय पहल की प्रशंसा की। इस विशेष अभियान के माध्यम से जोरहाट, टियोक, शिवसागर, नाजिरा, चराइदेव, सिमलुगुड़ी और सोनारी सहित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, आवश्यक वस्तुएं तथा विशेष रूप से दवाइयों का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में लोकप्रिय गायक कृष्णमणि नाथ सहित राज्य और जिले

के कई अन्य कलाकार भी उपस्थित रहे। इधर, जिले के काछमारी निवासी बालक शुभ्र किंकर (जोनाक)ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अपनी गुल्लक में कई वर्षों से जमा की गई पूरी बचत मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दी। उसने यह राशि जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा को औपचारिक रूप से सौंपी तथा मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र भी भेजा। जिला आयुक्त ने शुभ्र किंकर की इस प्रेरणादायक पहल की सराहना करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में समाज के प्रति उसकी संवेदनशील सोच पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश है।

संपादकीय

एक बेमानी, संसदीय बहस

लोकसभा में पेपर लीक के संशोधित बिल पर चर्चा बुधवार को भी जारी रही। उससे पहले 9 घंटे, देर रात, तक सदन में चर्चा होती रही और ठोस सुझावों के बिना राजनीतिक कीचड़ उछाला जाता रहा। बहस के समाहार में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री या नए शिक्षा मंत्री जो भी जवाब देंगे, वह भी 'राजनीतिक' ही होगा, लिहाजा उसका विश्लेषण बाद में करेंगे। विडंबना यह है कि पेपर लीक, शिक्षा-सुधार, परीक्षा-प्रणाली में सुधार और समग्रतः भारत की शिक्षा-व्यवस्था पर संसद जैसे सर्वोच्च, लोकतांत्रिक मंच पर बहस रखी गई थी, लेकिन एक भी सांसद ने सुझाव नहीं दिया कि बदलाव कैसे संभव है? कांग्रेस भाजपा को कोसती रही, समाजवादी पार्टी और बची-खुची तृणमूल कांग्रेस ने भी भाजपा-एनडीए सरकार को 'नाकाम' करार दिया, आतंकवाद और आपातकाल सरीखी अप्रासंगिक, उत्तेजक स्थितियों का भी जिक्र किया गया, आईआईटी मद्रास के निदेशक एवं अपने क्षेत्र के विख्यात विद्वान प्रो. कामकोटि को 'गोमूत्र विशेषज्ञ' करार दिया गया, लेकिन किसी ने यह सुझाव नहीं दिया कि पेपरलीक और उसके राज्यों में फैले माफिया पर काबू कैसे पाया जा सकता है। कुछ सांसद अपवाद हो सकते हैं, लेकिन वे 'नक्कारखाने में तूती' समान ही होंगे! सारांशतः हम इस बहस को 'बेमानी' मानते हैं। हमें लगता है कि पेपर लीक किसी भी राजनीतिक दल की बुनियादी चिंता नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर ये युवा, छात्र आंदोलन की आड़ में छिप कर मौजूदा मोदी सरकार और भाजपा पर राजनीतिक हमले करने की रणनीति पर जरूर सक्रिय हैं। भाजपा सांसद भी जवाहर लाल नेहरू से लेकर डॉ. मनमोहन सिंह तक की कांग्रेस सत्ताओं को 'नकारा', 'शिक्षा-विरोधी' करार देने में जुटे रहे। दरअसल पेपरलीक के मुद्दे पर ही वोट नहीं मिलते, लेकिन देश की युवा-शक्ति इतनी व्यापक है कि किसी भी सत्ता की चूलें हिला सकती है और किसी को भी सत्ता में ला सकती है। एक भी सांसद ने हमारी शिक्षा-व्यवस्था के 'काले, अद्धसत्य यथार्थ' को संसद में पेश नहीं किया कि हम कागजी डिग्रियों वाले, बेरोजगार स्नातक पैदा करने वाले देश हैं। दरअसल भारतीय शिक्षा-प्रणाली ज्ञान और कौशल के बजाय रटने की पद्धति, अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धा और नंबरों की अंधी दौड़ पर आधारित है, नतीजतन देश में स्नातक तो 13 गुना बढ़े हैं, लेकिन बेरोजगार भी 16 गुना बढ़े हैं। जेन-जी की उम्र 15-29 साल के करीब 32.2 करोड़ युवा आज भी 'बेरोजगार' हैं। क्या इसे ही 'जनसांख्यिकीय लाभांश' माना जाता है? सांसदों को उन बेरोजगारों की चिंता क्यों होगी? वे उनके परिजन थोड़े ही हैं! एक भी सांसद ने यह उल्लेख नहीं किया कि देश की बेरोजगारी दर 16.2 फीसदी से भी आगे बढ़ रही है। देश की करीब 69 फीसदी आबादी 15-64 साल के आयु-वर्ग की है। कमोबेश यह उम्र काम करने योग्य मानी जाती रही है, लेकिन काम, रोजगार, नौकरी ही उपलब्ध नहीं है। सरकारी नौकरी सिर्फ 4-5 फीसदी लोगों को ही नसीब है और निजी, असंगठित क्षेत्र में 95-96 फीसदी रोजगार, नौकरियां हैं। वहां वेतनमान, दिहाड़ी, काम करने के मूल्य बेहद असंतुलित हैं, लिहाजा युवाओं की भीड़ सरकारी नौकरी की अंधी दौड़ में शामिल होने को विवश है। सरकारी नौकरी नहीं मिलती या उम्र निकलने लगती है, तो युवा आत्महत्या करने लगते हैं अथवा अपराध का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। क्या संसदीय बहस के दौरान इन सच्चाइयों को उठाया गया? क्या इन पहलुओं पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? आश्चर्य यह है कि बेरोजगारी दर सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल-में सबसे अधिक 18.2 फीसदी है। तेलंगाना में भी कांग्रेसशासित राज्य है, वहां भी बेरोजगारी दर 18 फीसदी के करीब है। पंजाब में केजरीवाल की 'आप' की सरकार है, वह शिक्षा-सुधारक पार्टी होने का दावा करती रही है, लेकिन वहां भी बेरोजगारी दर 17 फीसदी के करीब है और आंध्रप्रदेश जैसे प्रौद्योगिकी वाले राज्य में भी 16.2 फीसदी बेरोजगारी है। पढ़-लिख लेंगे, नीट भी पास कर लेंगे, परीक्षक, परास्नातक भी हो जाएंगे, लेकिन रोजगार के अवसर कहां हैं? सरकार और उद्योगपति इस तथ्य पर मत इतराएं कि देश में अरबपति 576 हो गए हैं। बड़ी ऊंची छलांग लगाई है, लेकिन देश में प्रति व्यक्ति आय औसतन कितनी है? सभी जानते हैं, लिहाजा अरबपति होना भी हमारी आर्थिक असमानता का 'विद्रूप सच' है।

> प्रधानमंत्री, गृहमंत्री या नए शिक्षा मंत्री जो भी जवाब देंगे, वह भी 'राजनीतिक' ही होगा, लिहाजा उसका विश्लेषण बाद में करेंगे। विडंबना यह है कि पेपर लीक, शिक्षा-सुधार, परीक्षा-प्रणाली में सुधार और समग्रतः भारत की शिक्षा-व्यवस्था पर संसद जैसे सर्वोच्च, लोकतांत्रिक मंच पर बहस रखी गई थी, लेकिन एक भी सांसद ने सुझाव नहीं दिया कि बदलाव कैसे संभव है? कांग्रेस भाजपा को कोसती रही, समाजवादी पार्टी और बची-खुची तृणमूल कांग्रेस ने भी भाजपा-एनडीए सरकार को 'नाकाम' करार दिया, आतंकवाद और आपातकाल सरीखी अप्रासंगिक, उत्तेजक स्थितियों का भी जिक्र किया गया, आईआईटी मद्रास के निदेशक एवं अपने क्षेत्र के विख्यात विद्वान प्रो. कामकोटि को 'गोमूत्र विशेषज्ञ' करार दिया गया, लेकिन किसी ने यह सुझाव नहीं दिया कि पेपरलीक और उसके राज्यों में फैले माफिया पर काबू कैसे पाया जा सकता है। कुछ सांसद अपवाद हो सकते हैं, लेकिन वे 'नक्कारखाने में तूती' समान ही होंगे! सारांशतः हम इस बहस को 'बेमानी' मानते हैं।

कुछ अलग

खुशियां हों हजार

परमात्मा ने कितना सुंदर सिस्टम बना रखा है। हम फिर भी भूले रहते हैं और परेशानियों भरा जीवन जीते हैं, दुखी होते हैं, रिश्ते खराब कर लेते हैं और सारी दुनिया को कोसते रहते हैं। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक खास कैमिकल रिलीज करता है जिसे रिवार्ड कैमिकल कहता है। यानी, आपने कोई कठिन काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, किसी क्लायंट से आपको आर्डर मिल गया, कोई डील फाइनल हो गई। अगर आप मैडिटेशन करें, हल्की दौड़ लगाएं, तैराकी करें या साइकलिंग करें, हल्की धूप में बैठें, प्रकृति के सान्निध्य में जाएं, यानी किसी प्राकृतिक स्थान पर जाएं, पेड़-पौधों, फूलों के बीच जाएं तो आपका दिमाग सीरोटोनिन नाम का कैमिकल रिलीज करता है जो आपका मूड सैट कर देता है। अगर आप अपने पेट्स के साथ खेलें, छोटे बच्चे के साथ खेलें, किसी प्रिय व्यक्ति का हाथ पकड़ें, किसी को गले लगाएं और किसी की सच्ची प्रशंसा करें या शाबाशी दें तो भी आप खुश हो जाते हैं क्योंकि तब हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन नाम का कैमिकल रिलीज करता है, जिसे वैज्ञानिक लोग लव कैमिकल मानते हैं। अगर आप कोई एक्सरसाइज करें या हंसें, लाफ्टर एक्सरसाइज करें, कोई कामेडी देखें या डार्क चाकलेट खाएं तो हमारा दिमाग एंडॉरफिन नाम का कैमिकल रिलीज करता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यह एक पेनकिलर का काम करता है जिससे हमें खुशी मिलती है। ये चार कैमिकल खुशी देने वाले कैमिकल हैं। खुश रहना हर दूसरा मंत्र यह है कि हम हर छोटी-बड़ी असहमति को युद्ध में न बदल दें।

शब्द शक्ति में श्लील और अश्लील को लेकर भाषा शास्त्री स्पष्ट विभाजन स्वीकार करते हैं

समाज को कहां ले जाएगी असभ्यता को सही साबित करने की कोशिश

गाली इन दिनों राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में हैं। जंतर-मंतर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दी खुलेआम गंदी गालियां इसका बहाना बनीं हैं। हैरत की बात है कि इसमें कई प्रोफेसर और पत्रकार भी शामिल हो गए हैं और इन गालियों को उचित ठहराने की दौड़ का हिस्सा बन गए हैं। इसे लड़कियों की क्रांतिकारी अभिव्यक्ति बताया जा रहा है तो कई गालीबाजों को नई गालियां रचने का सुझाव दे रहा है। उनके हिसाब से सारी गालियां पुरूषों द्वारा रची गई हैं, लिहाजा लड़कियों को नई तरह की गाली पुराण रचना चाहिए। इसके खिलाफ का समाज का एक बड़ा तबका इस नई प्रवृत्ति की मुखालफत कर रहा है। उसका कहना है कि गालियां भले हीं समाज में सदा से चली आ रही हैं, लेकिन कम से कम उनकी सार्वजनिक स्वीकृति नहीं रही है। गालियों के समर्थकों में सबसे बड़ी संख्या खुद को क्रांतिकारी मानने वाले वामपंथी हैं। प्रगतिशील लेखक संघ भारत में वामपंथी विचारधारा के लिहाज से गठित हुआ था। उसके पहले अध्यक्ष उपन्यास सम्राट प्रेमचंद थे। गाली विमर्श के संदर्भ में प्रेमचंद का लिखे एक लेख का अंश याद आ रहा है। उन्होंने लिखा है, ''हर जाति का बोलचाल का ढ़ंग उसकी नैतिक स्थिति का पता देता है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो हिन्दुस्तान सारी दुनिया की तमाम जातियों में सबसे नीचे नजर आएगा। बोलचाल की गंभीरता और सुथरापन जाति की महानता और उसकी नैतिक पवित्रता को व्यक्त करती है और बदजवानी नैतिक अंधकार और जाति के पतन का पक्का प्रमाण है। जितने गन्दे शब्द हमारी जबान से निकलते हैं शायद ही किसी सभ्य जाति की ज़बान से निकलते हों।''इसमें दो राय नहीं कि हर सफल आंदोलन के बाद आंदोलनकारी नायक और विजेता के रूप में उभरते हैं। इस लिहाज से काकरोच जनता पार्टी के नेता जंतर-मंतर आंदोलन के फिलहाल के विजेता तो हैं हीं। इस तर्क से उनका साथ देने वाला वाला समूह भी उसी वर्ग का माना जाएगा। इतिहास हमेशा विजेताओं का ही गुणगान करता है, उसकी सफलता की बलैया लेता है। चूंकि काकरोच जनता पार्टी के नेता चूंकि हीरो हैं, इसलिए उनकी ओर से दी गई गालियों को उनके गुणों के रूप में देखने की कोशिश हो रही है। तर्क दिया जा रहा है कि भारतीय समाज में शादी-ब्याह और मुंडन-जनेऊ के मौके पर प्यार से गालियां दी जातीं हैं। लिहाजा से जंतर-मंतर की गालियां भी उन्हीं गालियों की तरह स्नेह की अभिव्यक्ति हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है ? गंभीरता से विचार करेंगे तो इसका जवाब ना में मिलता है। इस अश्लील अभिव्यक्ति का मकसद देश के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए हिकारत और घृणा का प्रदर्शन है। मोदी देश के वामपंथी और कांग्रेसी इकोसिस्टम एवं संस्कृति और परंपराभंजकों के निशाने पर तब से हैं, जब आज के जेन जी के अधिसंख्य जन्मे भी नहीं होंगे। अतीत में मोदी के खिलाफ कठोर शब्दों का इस्तेमाल जरूर होता था, लेकिन उनमें गालियां नहीं थीं। जंतर-मंतर का हालिया आंदोलन इसी बुनियाद पर आगे की कड़ी है। बचाव में उतरे वामपंथियों का तर्क है कि ये गालियां नई नहीं हैं। कई तो खुद का उदाहरण देते हुए कहने से नहीं चूक रहे कि वे भी गाली देते हैं या फिर उनके दोस्तों के बीच गालियों का खूब आदान-प्रदान होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे ऐसी ही गालियां अपने ही बच्चों के मुख से अपने ही घरों में सुनना पसंद करेंगे। सवाल यह भी है कि क्या इन गालीबाजों को भविष्य में वे अपने परिवार का दामाद या बहू के रूप हिस्सा बनाना पसंद करेंगे। सवाल यह भी है कि क्या वे अपने ही बच्चों से स्नेह के तौर पर अपने ही माता-पिता को ऐसी गालियां दिलाना स्वीकार करेंगे। निश्चित तौर पर इन सवालों का जवाब ना में है। हर समाज में गालियां किसी न किसी रूप में रही हैं। लेकिन वे कभी सार्वजनिक स्वीकार्यता और विमर्श का विषय नहीं रही हैं। गालियां संस्कार से जुड़ी हैं। भाषाशास्त्री शब्द शक्ति की बात करते हैं। शब्द शक्ति में श्लील और अश्लील को लेकर भाषा शास्त्री स्पष्ट विभाजन स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि श्लील ही सार्वजनिक चर्चा और अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। आधुनिक साहित्य में गालियों का प्रयोग वामपंथी विचारधारा के बढ़ते असर के साथ बढ़ा। लेकिन प्रेमचंद के किसी कहानी या उपन्यास में कहीं गाली या अश्लील शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। सच तो यह है कि गालियां कभी यथार्थ नहीं होती। हिंदी साहित्य में यथार्थवाद की अभिव्यक्ति के लिए गालियों के प्रयोग की शुरूआत हुई। लेकिन आधुनिक यथार्थवादी चिंतन से पहले के साहित्य में कभी गालियों का प्रयोग नहीं होता दिखता। अनुवादटूल और संसाधन तर्क दिया जा रहा है कि जेन जी की यही भाषा है। वह ऐसे ही खुद को अभिव्यक्त करता है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि क्या वह परीक्षा में भी वह गालियों को अपनी जवाब में शामिल करता है?और क्या वह स्वीकार्य होगा? उनके समर्थन में उतरे दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक कक्षाओं में गालियों के धाराप्रवाह प्रयोग को स्वीकार करेंगे। सवाल यह भी है कि जो पत्रकार इसका समर्थन कर रहे हैं, क्या वे अपने अखबारों और अपने स्टूडियो में उन गालियों के इस्तेमाल को तैयार होंगे? निश्चित तौर पर इन सभी सवालों का जवाब ना में है। फिर यह सवाल क्यों ना उठे कि गालियों का महिमा मंडन क्यों? तर्क यह भी है कि जेन जी इसी तरह सोचता है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि समूचे देश का जेन जी एक जैसा नहीं है, उसकी एक मातृभाषाएं नहीं है। जरूरी नहीं कि दिल्ली और चंडीगढ़ के जेन जी की तरह मुंबई और बंगलुरू का जेन जी भी सोचता हो। जिस तरह हर इलाके के लिए लोगों का खान-पान, रहन-सहन और बोली-बानी अलग-अलग हैं, कुछ इसी तरह हर इलाके के जेन जी की सोच भी अलग है। कुछ हजार या लाख जेन जी भले ही गालियां देने में फख्र महसूस कर रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी देश के जेन जी का बड़ा हिस्सा संस्कारी है और उसे सार्वजनिक तौर पर गालियां बकने से परहेज है। मार्क्सवादी हिंदी लेखक जगदीश्वर चतुर्वेदी ने एक जगह लिखा है कि गालियों को वैध ठहराने की कोशिश पुनरूत्थानवादी सोच की खूबी है। वह पुराने असभ्य रूपों, भाषिक प्रयोगों, आदतों और संस्कारों को बनाये रखता है। मार्क्सवादी राष्ट्रीय विचारधारा को पुनरूत्थानवादी ही मानते हैं। तो क्या मान लें कि गालियों को उचित ठहराने वाले मार्क्सवादी भी अब पुनरूत्थानवादी हो गए हैं? समूचे भारतीय इतिहास और साहित्य में कहीं क्या गाली दी जाती थी, इसका प्रयोग नहीं दिखता। गालियां हमेशा से गलत और असभ्य मानी जाती रही हैं। महाभारत में शिशुपाल का प्रकरण आता है। जिसकी सौ गालियों को कृष्ण बर्दाश्त करते हैं, लेकिन शिशुपाल जब सौ की सीमा पार करता है तो उसका वध कर देते हैं। जाहिर है कि कृष्ण के दौर में गालियां असभ्यता की निशानी थी। उनका महिमा मंडन नहीं होता था। मध्यकाल में जरूर गालियों को प्रतिष्ठा मिलने के संकेत मिलते हैं। फिर भी उनकी सार्वजनिक स्वीकार्यता नहीं दिखती। ऐसे में प्रश्न यह है कि भारतीय समाज प्रधानमंत्री को सार्वजनिक तौर पर दी जाने वाली गालियों और असभ्यता को क्यों स्वीकार किया जाए? नई पीढ़ी को असभ्य बनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा क्यों दिया जाए। सभ्यता के साथ भी कड़ी से कड़ी आलोचना करने और कठोर बातें बोलने के लिए उन्हें योग्य क्यों न बनाया जाए। उनके परिवारों को क्यों न चेताया जाए कि असभ्यता की ओर बढ़ रहे अपने बच्चों के कदम को रोकें और उन्हें जिम्मेदार नागरिक और परिवारी बनाने की दिशा में आगे बढ़ें।

> किरोच जनता पार्टी के नेता जंतर-मंतर आंदोलन के फिलहाल के विजेता तो हैं हीं। इस तर्क से उनका साथ देने वाला वाला समूह भी उसी वर्ग का माना जाएगा। इतिहास हमेशा विजेताओं का ही गुणगान करता है, उसकी सफलता की बलैया लेता है। चूंकि काकरोच जनता पार्टी के नेता चूंकि हीरो हैं, इसलिए उनकी ओर से दी गई गालियों को उनके गुणों के रूप में देखने की कोशिश हो रही है। तर्क दिया जा रहा है कि भारतीय समाज में शादी-ब्याह और मुंडन-जनेऊ के मौके पर प्यार से गालियां दी जातीं हैं। लिहाजा से जंतर-मंतर की गालियां भी उन्हीं गालियों की तरह स्नेह की अभिव्यक्ति हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है ? गंभीरता से विचार करेंगे तो इसका जवाब ना में मिलता है। इस अश्लील अभिव्यक्ति का मकसद देश के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए हिकारत और घृणा का प्रदर्शन है।

देश दुनीया से

बदलता भूजल प्रवाह बढ़ाता भवनों के लिए जोखिम

पर्वतीय भूमिगत जल भंडारों पर वैश्विक स्तर पर भी बहुत विस्तृत अध्ययन कई कारणों से नहीं हो पाया है। उत्तराखंड जैसे घोषित पर्वतीय राज्य में भी यही स्थिति है। किंतु जोशीमठ भूधंसाव से बनी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं तथा पहाड़ी नए-पुराने शहरों को बचाने-बसाने के क्रम में भूजल विज्ञान की जमीनी समझ अपरिहार्य हो गई है। जोशीमठ में 2 जनवरी, 2023 से एक कॉलोनी के चैनल से पानी निकलने की सूचना मिलने के बाद से ही सरकारी स्तर पर इसकी प्रतिदिन माप की जा रही है और तब से जलप्रवाह में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। बयान जारी होते रहे हैं कि पानी के प्रवाह की दर इतनी कम हुई या इतनी ज्यादा हुई, या अब एकदम ही बंद हो गई है। पानी लोगों के घरों में भी दरारों के साथ आया था। ऐसे बयानों से आमजन के बीच यह धारणा विकसित करने की कोशिश होती है कि कम होता डिस्चार्ज भूधंसाव का जोखिम कम होने का सूचक है। ऐसा विश्लेषण करना वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं होगा। यदि निर्माणों को आधार देने वाली परतों में जल रिसाव या जल निकासी घटती-बढ़ती रहती है अथवा चट्टानों के अपभ्रंशों में पानी सूखता-भरता रहता है, यानी उतार-चढ़ाव होता है, तो आधारित भवनों की नींवों पर काफी दबाव आ जाता है। भूजल की तेजी से अप्रत्याशित घटत-बढ़त भवनों को लंबी अवधि में कमजोर ही करती है। यदि यह बाहर निकलता कम पानी पहले कहीं नींवों के आसपास जमा होने के कारण कम हो रहा है, तो वह भवनों की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। नींव के आसपास जमा पानी मृदा परतों की ताकत कम कर देता है। पहाड़ों में, खासकर चूने के अपभ्रंशों में भी पानी घुसता व जमा होता है। ठोस चट्टानों की दरारों से भी पानी घुसता है। घने जंगलों के चौड़ी पत्तियों वाले क्षेत्र में भी भूमिगत जल जमा होता है। रिसाव बर्फबारी से भी संभव है। अनुभव रहा है कि जब कभी अचानक नदी की धारा मंद हो जाती है, तो अंदेशा पैदा हो जाता है कि कहीं ऊपर नदी मार्ग में भूस्खलनों से अवरोध आ गया है। अब पानी कम दिख रहा है, किंतु जब वह अवरोध टूटेगा, तो नदी भीषण वेग में आ सकती है। जलवायु बदलाव की अतिरेकी घटनाओं के बीच ऐसे दंश बढ़ेंगे ही। कई बार गहराइयों तक पहुंची नींवों से भी पहाड़ों में जमीन के अंदर ढलानों में बहता जल-प्रवाह बाधित हो जाता है। ऐसे में जलधाराएं अन्य राहें ढूंढ़ लेती हैं व अन्य कमजोर भ्रंशों से फूटकर बाहर निकल सकती हैं। जमीन के भीतर यदि ढीली मिट्टी-पत्थर की परतें हों, तो जैसे सतह पर ढलानों में वेगमयी जल-प्रवाह मलबा-मिट्टी लेकर बढ़ता है, वैसे ही वे जमीन के भीतर भी मिट्टी-पत्थर लेकर बढ़ सकते हैं और मकानों, भवनों व पिलरों की नींव की मिट्टी बहाकर आगे ले जा सकते हैं। नींव के मेटिरियल के कटाव से मकान, भवन, पुल आदि तिरछे या ध्वस्त हो सकते हैं। यदि भवनों के आसपास किन्हीं कारणों से दरारें आ जाएं, तो भूमिगत नींवों के पास पहुंचा पानी भी मकानों, भवनों या अन्य कंक्रीट ढांचों को असुरक्षित व जर्जर बना सकता है। निर्माण संरचनाओं की नींवों के जितना निकट भूमिगत जल स्तर होता जाता है, उतनी ही नींव की भवन धारण क्षमता घटती जाती है। भूमिगत जल जितना नीचे होगा, उतना ही कम उसका असर निर्माण संरचनाओं पर पड़ेगा। शैल या मृदा परतों के रंध्रों में पहुंचा पानी पोर प्रेशर पर असर डालता है। यदि रंध्रों में पानी हवा को हटाकर अपनी जगह बना रहा है, तो पानी, वायु से भारी होने के कारण, शैल या मिट्टी की परतों का भार बढ़ा देता है। इससे सतह व भीतर के ढलावों (स्लोप्स) में अस्थिरता आ जाती है, जिससे निर्माणों में भी अस्थिरता आ सकती है। साथ ही, पानी जब किसी शैल या मृदा परत पर रिसता रहता है, तो वह उस परत के भौतिक व रासायनिक घटकों में बदलाव ले आता है। यदि शौचालय सीवर लाइनों से जुड़े नहीं हैं और उनका मल-मूत्र एवं शौच-जल परिसर में बने पिटों में ही जाता है, तो अत्यधिक उपयोग की स्थिति में भूमि के भीतर नींवों के आसपास रिसाव और जल-जमाव की समस्या पैदा हो सकती है। अधिकांश गांवों व बस्तियों में शौचालय सीवर नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं, इसलिए यह जोखिम वहां भी विद्यमान है। ऐसे में यदि किसी स्थान पर सामान्य क्षमता से अधिक भीड़ शौचालयों और मूत्रालयों का उपयोग करे, तो पिटों पर अत्यधिक दबाव पड़ना, उनका क्षतिग्रस्त होना तथा रिसाव की समस्या बढ़ना स्वाभाविक है। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुमंजिला भवनों के निर्माण के लिए गहरी नींव आवश्यक होती है, जिससे भूमिगत जलवाहिनियों को क्षति पहुंचने या उनके प्राकृतिक प्रवाह में परिवर्तन की आशंका बढ़ जाती है। जोशीमठ जैसे क्षेत्रों में वर्षों से जारी असमान भू-धंसाव के कारण सतही और भूमिगत जल के प्रवाह तथा रिसाव की दिशा भी बदल सकती है। जिन इलाकों में भू-धंसाव हो रहा है, वहां खासकर बरसात में अधूरी नालियां या अन्य प्रकार के खदान के काम नहीं छोड़े जाने चाहिए। यदि नदियों में, बैराज-बांधों में, सुरंगों के मुहानों पर मलबे के अंबारों के अवरोध खड़े कर दिए हों, तो उनसे भी पानी रिसकर पार्श्व की संरचनाओं में जा सकता है। जोशीमठ धंसाव से जुड़ी सरकारी उपग्रह तस्वीरें भले ही सार्वजनिक वेबसाइट से हटा दी गई हों, लेकिन ग्रीस के एक शोध संस्थान के सैटेलाइट विश्लेषण, जिसे भारत के एक प्रतिष्ठित प्रकाशन ने प्रकाशित किया, के अनुसार 2018 से 31 दिसंबर, 2022 तक जोशीमठ औसतन लगभग 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से धंसता रहा।

आप का नजरीया

भूमि की फर्जी खरीद

जमीनों की खरीद में एक पूरा माफिया सक्रिय है और धारा 118 के सीधे उल्लंघन के निशान लिए पूरा पहाड़ा भरभरा रहा है। मामला गगल एयरपोर्ट के साथ और भी संगीन हो गया जब जम्मू से आकर बसा परिवार सौ कनाल जमीन पर हिमाचली घोषित हो गया। आश्चर्य यह कि जहां चंद मरले जमीन की खरीद मुश्किल है, वहां जम्मू से आए दंपती ने सौ कनाल पर कब्जा जमा लिया। पूरे प्रदेश में भूमि बिक्री के कई हॉट स्पॉट बने हैं, तो इसलिए कि एक पूरा तंत्र विकसित हो गया है। जाहिर है यह भू-राजस्व विभाग की मिलीभगत और राजनीतिक प्रश्रय के बिना असंभव है। यहां लैंड सीलिंग कानून के बाद पैदा हुए लैंड लाड्र्स की उत्पत्ति का भी एक लंबा सिलसिला रहा है। शहर बड़े हुए, लेकिन शहरीकरण अंगीकार नहीं हुआ। खेत बिकते रहे, लेकिन कृषि बचाने के कानून नहीं बने। मुजारा कानून के तहत लघु जमींदार खत्म हुए, लेकिन जिन्हें जमीनें मिली, वे सौदा करते रहे। इसी तरह नौतोड़ जमीनों का आबंटन भी कृषि उपज के बजाय भूमि के सौदों का जरिया बन गया। सामाजिक उत्थान के इरादों से आए लैंड सीलिंग एक्ट ने जमीनों की बिक्री खोल दी। नतीजतन कांगड़ा घाटी, कुल्लू वैली, हमीरपुर, मंडी तथा बिलासपुर के कृषि योग्य खेत कंक्रीट उगाने लगे। अगर जमीनें छीनीं गईं, तो शर्त यह होनी चाहिए थी कि इनका उपयोग खेतीबाड़ी के लिए ही होगा। जमीनों की बिक्री दरअसल कृषि-बागबानी के प्रति घटता मोह भी है। वन संरक्षण अधिनियम की कमजोरी के कारण भी मानव गतिविधियों का भावार्थ बदल गया है। बंदर व वन्य प्राणियों के कारण खेतों पर कृषि बंद हो गई और बागीचे ठूंठ बन गए। व्यापारिक गतिविधियों में स्वरोजगार की तलाश के कारण और पर्यटन के अंधाधुंध प्रसार के कारण भी जमीनों की बिक्री का माफिया पैदा हो गया। पर्यटन जिस तरह पहाड़ की ओर चढ़ रहा है, उससे भूमि की बिक्री अब जलस्रोतों के नजदीक, जल रिसाव के पास तथा ढांग पर होने लगी है। यही वजह है कि मनाली, कसौली, डलहौजी, मकलोडगंज, नयनादेवी, कुल्लू, मंडी व अन्य अनेक शहरों के नीचे बिक रही जमीनें, इनके वजूद को बर्बाद कर रही हैं। जाहिर है इस स्थिति के लिए शहरी विकास विभाग, ग्राम एवं नगर योजना विभाग, भू-राजस्व विभाग, पर्यटन विभाग, स्थानीय प्रशासन तथा राजनीतिक संस्थाएं दोषी हैं। शहरीकरण के सांचे में गगल एयरपोर्ट का विकास भू-माफिया की ताकत बन जाता है, लेकिन हिमुडा को नए शहर बसाने की फुर्सत नहीं मिलती। पहले चैतड़ू के पास सेटेलाइट टाउन बसाने की योजना राजनीतिक कारणों से बर्बाद हुई, फिर नरघोटा में एक नए शहर की संभावना को समाप्त किया गया। नरघोटा में टाउनशिप के लिए मांग का जबरदस्त आधार था, लेकिन पूरी परियोजना को शहीद कर दिया गया। अगर भू-माफिया की पड़ताल हो तो राजनीति के कई चेहरे, ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही के कई हाथ, ठेकेदारों की पूरी जमात तथा टीसीपी के उल्लंघन करते कई लोग सामने आ जाएंगे। हिमाचल को भू-माफिया से बचाने की राजनीतिक इच्छा तब ही जाहिर होगी अगर पूरे प्रदेश को टीसीपी कानून के तहत लाया जाए, आवासीय व्यवस्था के तहत नए शहर, नई बस्तियां बसाई जाएं तथा लैंड पूलिंग के तहत गैर कृषि योग्य जमीन तथा वन भूमि को भी लाया जाए। शहरों के दायरे तथा विकास के मुहानों पर नवनिर्माण को प्रतिबंधित करके कुछ हद तक बचाव होगा, वरना हिमाचल में जमीनों की खरीद-फरोख्त का धंधा फलता- फूलता रहेगा। इसलिए एयरपोर्ट, मंदिर, मेडिकल कालेज तथा संस्थानों की स्थापना के साथ नव विकास के पूरे क्षेत्र को 'साडा' घोषित करना चाहिए।

> आश्चर्य यह कि जहां चंद मरले जमीन की खरीद मुश्किल है, वहां जम्मू से आए दंपती ने सौ कनाल पर कब्जा जमा लिया। पूरे प्रदेश में भूमि बिक्री के कई हॉट स्पॉट बने हैं, तो इसलिए कि एक पूरा तंत्र विकसित हो गया है। जाहिर है यह भू-राजस्व विभाग की मिलीभगत और राजनीतिक प्रश्रय के बिना असंभव है। यहां लैंड सीलिंग कानून के बाद पैदा हुए लैंड लाड्र्स की उत्पत्ति का भी एक लंबा सिलसिला रहा है। शहर बड़े हुए, लेकिन शहरीकरण अंगीकार नहीं हुआ। खेत बिकते रहे, लेकिन कृषि बचाने के कानून नहीं बने। मुजारा कानून के तहत लघु जमींदार खत्म हुए, लेकिन जिन्हें जमीनें मिली, वे सौदा करते रहे। इसी तरह नौतोड़ जमीनों का आबंटन भी कृषि उपज के बजाय भूमि के सौदों का जरिया बन गया। सामाजिक उत्थान के इरादों से आए लैंड सीलिंग एक्ट ने जमीनों की बिक्री खोल दी। नतीजतन कांगड़ा घाटी, कुल्लू वैली, हमीरपुर, मंडी तथा बिलासपुर के कृषि योग्य खेत कंक्रीट उगाने लगे। अगर जमीनें छीनीं गईं, तो शर्त यह होनी चाहिए थी कि इनका उपयोग खेतीबाड़ी के लिए ही होगा। जमीनों की बिक्री दरअसल कृषि-बागबानी के प्रति घटता मोह भी है। वन संरक्षण अधिनियम की कमजोरी के कारण भी मानव गतिविधियों का भावार्थ बदल गया है। बंदर व वन्य प्राणियों के कारण खेतों पर कृषि बंद हो गई और बागीचे ठूंठ बन गए। व्यापारिक गतिविधियों में स्वरोजगार की तलाश के कारण और पर्यटन के अंधाधुंध प्रसार के कारण भी जमीनों की बिक्री का माफिया पैदा हो गया। पर्यटन जिस तरह पहाड़ की ओर चढ़ रहा है, उससे भूमि की बिक्री अब जलस्रोतों के नजदीक, जल रिसाव के पास तथा ढांग पर होने लगी है।

दृष्टि कोण

राष्ट्रहित में नियमित सैन्य भर्ती जरूरी

जून 2026 के अंतिम सप्ताह में देश के विभिन्न सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों से अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड के वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से चर्चा में रहे। प्रशिक्षण पूरा कर घर लौटते इन युवा सैनिकों का गांवों और शहरों में जिस आत्मीयता और सम्मान के साथ स्वागत हुआ, उसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। कहीं माता-पिता अपने बेटे को सैनिक की वर्दी में देखकर भावुक हुए, तो कहीं फूलमालाओं और बैंड-बाजों के साथ उनका अभिनंदन किया गया। इन दृश्यों ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि भारतीय समाज में सैनिक केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि राष्ट्रसेवा, अनुशासन और त्याग का प्रतीक हैं। इन भावनात्मक दृश्यों के साथ अग्निपथ योजना को लेकर एक गंभीर बहस भी तेज हुई। प्रश्न यह है कि क्या चार वर्ष की संविदा आधारित भर्ती व्यवस्था भारत की दीर्घकालीन सुरक्षा आवश्यकताओं और युवाओं के सुरक्षित भविष्य के अनुरूप है, अथवा इसमें आवश्यक सुधारों का समय आ गया है? भारत सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना को मंजूरी दी और 16 जून 2022 को इसकी घोषणा की। इसके अंतर्गत 17 से 21 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की चार वर्ष के लिए भर्ती की जाती है। पहले वर्ष लगभग 30 हजार रुपए मासिक वेतन मिलता है, जो चौथे वर्ष तक लगभग 40 हजार रुपए हो जाता है। वेतन का 30 प्रतिशत भाग सेवा निधि में जमा होता है, जिसमें सरकार भी समान राशि का योगदान देती है। सेवा अवधि पूरी होने पर लगभग 11.7 लाख रुपए की कर-मुक्त सेवा निधि, लगभग 48 लाख रुपए का जीवन बीमा तथा कौशल प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार लगभग 25 प्रतिशत अग्निवीरों को प्रदर्शन, योग्यता और रिक्तियों के आधार पर नियमित सेवा में रखा जाना है, शेष 75 फीसदी अग्निवीरों को 4 साल बाद सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, जिसके बाद उनके करियर और स्थायी रोजगार को लेकर भारी अनिश्चितता रहना तय है, दूसरे चार साल बाद बाहर होने वाले जवानों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा, आजीवन पेंशन या स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जो पहले स्थायी सैनिकों को मिलती थीं। कई राज्य सरकारों ने पुलिस और अन्य सेवाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है तथा निजी क्षेत्र की अनेक कंपनियों ने भी उन्हें रोजगार देने में रुचि दिखाई है। योजना के इन सकारात्मक पक्षों के बावजूद अनेक रक्षा विशेषज्ञों और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। उनका मानना है कि आधुनिक सैनिक तैयार करने की प्रक्रिया केवल हथियार चलाने का प्रशिक्षण नहीं है। सामरिक सोच, नेतृत्व क्षमता, रेजिमेंटल परंपराओं, टीम भावना, मानसिक दृढ़ता और युद्धक्षेत्र में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विकसित होने में कई वर्ष लगते हैं। इसलिए चार वर्ष की सेवा अवधि अपेक्षाकृत कम मानी जानी चाहिए। आज भारत के सामने सुरक्षा चुनौतियां पहले से कहीं अधिक जटिल हैं। उत्तरी सीमा पर चीन के साथ तनाव, पश्चिमी सीमा पर आतंकवाद, ड्रोन के बढ़ते खतरे, साइबर हमले और तकनीक आधारित युद्ध ने सैन्य तैयारियों का स्वरूप बदल दिया है। ऐसे समय में सेना को ऐसे सैनिकों की आवश्यकता है जो आधुनिक तकनीक के साथ-साथ लंबा व्यावहारिक अनुभव भी रखते हों। रेजिमेंटल भावना भी भारतीय सेना की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। यह केवल प्रशिक्षण से नहीं, बल्कि वर्षों तक साथ सेवा करने, कठिन परिस्थितियों का सामना करने और आपसी विश्वास से विकसित होती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि चार वर्ष की सेवा अवधि इस भावना को किस सीमा तक प्रभावित करेगी, इसका आकलन दीर्घकालिक अनुभव और सैन्य अध्ययनों के आधार पर ही किया जा सकेगा।

बेअदबी कानून बनाने में पंजाब सरकार ने दिखाई गैर-संजीदगी : जत्थेदार गडगज

चंडीगढ़(हिंस)। अकाल तख्त साहिब के निर्देश पर बेअदबी कानून में संशोधन किये जाने के बाद जत्थेदार कुलदीप सिंह गडगज ने कहा है कि पंथ गुरु साहिब के हुक्म के अनुसार चलता है। गुरु पंथ की सहमति के बिना कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। पंजाब सरकार ने इस मामले में गैर-संजीदगी दिखाई है। पंजाब सरकार की तरफ से बुधवार को संशोधित कानून का ड्राफ्ट अकाल तख्त सचिवालय को सौंपा गया था। गुरुवार को अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गडगज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज पूरी दुनिया में गुरबाणी को मानने वाले सिख मौजूद हैं, इसलिए ऐसा कोई भी कानून स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसे गुरु पंथ की मंजूरी प्राप्त न हो। इसी उद्देश्य से पिछले महीने पंजाब सरकार के विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों को श्री अकाल तख्त साहिब बुलाया गया था। वहां पारदर्शिता के साथ इस मुद्दे पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने जयकारे लगाकर आपत्तियों को दूर करने तथा आवश्यक संशोधन करने पर सहमति जताई थी। जत्थेदार ने कहा कि बैठक में विशेष रूप से *कस्टोडियन* शब्द को हटाने, *बीड़* शब्द को स्पष्ट रूप से शामिल करने और बेअदबी के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इसका उद्देश्य दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना था। जत्थेदार के अनुसार, इन सभी बिंदुओं पर आम सहमति बनने के बाद पंजाब सरकार से संशोधित मसौदा भेजने को कहा गया था। जत्थेदार गडगज ने कहा कि पंजाब सरकार को 28 जुलाई तक संशोधित मसौदा भेजने का समय दिया गया था, लेकिन तय समय सीमा तक सरकार की ओर से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद 29 जुलाई को सरकार ने आधिकारिक संशोधित मसौदा भेजा। सरकार की ओर से भेजे गए संशोधित मसौदे का अध्ययन करने के बाद सामने आया कि जिन प्रमुख आपत्तियों को दूर करने की बात हुई थी, उनमें अपेक्षित बदलाव नहीं किए गए हैं। जत्थेदार ने कहा कि बीड़ शब्द को शामिल करने और कस्टोडियन शब्द हटाने की मांग पर सरकार ने यह कहते हुए संशोधन नहीं किया कि यह उसके अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। सरकार ने कस्टोडियन शब्द को लेकर विस्तृत स्पष्टीकरण जरूर दिया है, लेकिन शब्द को हटाया नहीं गया। वह अभी भी मसौदे में पहले की तरह मौजूद है। जिन प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनी थी, उनमें से करीब 90 प्रतिशत बातों को स्वीकार नहीं किया गया है। जत्थेदार ने कहा कि जब तक बेअदबी कानून में प्रस्तावित संशोधनों पर अंतिम सहमति नहीं बन जाती, तब तक 3 अगस्त से शुरू होने वाले पंजाब विधानसभा सत्र में इस कानून को लेकर किसी भी तरह की बहस या चर्चा नहीं की जानी चाहिए। पहले श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से उठाई गई आपत्तियों और दिए गए सुझावों पर सहमति बनना जरूरी है।

सिख विरोधी दंगों में दस हजार से ज्यादा सिख भाई-बहन मारे गए थे : केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ (हिंस)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगों में करीब तीन हजार व समूचे देश में दस हजार से ज्यादा बेकसूर सिख भाई-बहन मारे गए थे। हत्या व दंगा-फसाद को उकसाने में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता *गांधी परिवार की छतरी* के नीचे काम करते थे। कुछ को उम्र कैद की सज़ा हुई और तबके कई के मामले अभी भी अदालत की चौखट पर हैं। उप मुख्यमंत्री ने गुरूवार को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हत्याओं को जायज़ ठहराने के लिए प्रधानमंत्री बनते ही राजीव गांधी ने मासूमियत से हत्यारों का बचाव करते हुए कहा था, *जब बड़ा पेड़ गिरता है, तब धरती हिलती है*। मतलब साफ था, तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी कांग्रेसी दंगाइयों को बचा रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिना ज्ञान के विशेषज्ञ राहुल गांधी को सबकुछ पता है, बस यही नहीं पता कि वे लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं।

बूथ जीतो, चुनाव जीतो के मंत्र पर जुटें कार्यकर्ता विपक्ष के भ्रम का दें जवाब : गिरीश चंद्र यादव

सुलतानपुर(हिंस)। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर में मिशन-2027 को लेकर भाजपा ने संगठन को पूरी तरह चुनावी मोड में उतरने का आह्वान किया। जिले के प्रभारी एवं उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव ने गुरुवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। श्री यादव ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता *बूथ जीतो, चुनाव जीतो* के मंत्र को धरातल पर उतारे। विपक्ष के झूठ और भ्रम फैलाने वाले नैरेटिव का तथ्यों के साथ जवाब दें तथा सोशल मीडिया पर प्रतिदिन सक्रिय रहकर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं। बैठक का आयोजन नगर के भाजपा कार्यालय के सभागार मे गुरुवार को किया गया। श्री यादव ने आगे कहा कि समर्पित कार्यकर्ताओं की बदौलत भाजपा आज 22 से अधिक राज्यों में सरकार चला रही है और मिशन-2027 भी कार्यकर्ताओं के दम पर ही सफल होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस नीट परीक्षा व राम मंदिर जैसे मुद्दों पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता उनके मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। कांग्रेस व सपा सनातन विरोधी दल हैं।तभी डिंपल यादव राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने की बात करती और कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व को नकारती थीं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार जनहित के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय रखने, पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने की। उन्होंने कहा कि संगठन पूरी तरह चुनावी मोड में कार्य कर रहा है और प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ स्तर तक सक्रिय रहना होगा। जिला मीडिया प्रमुख विजय रघुवंशी ने बताया कि बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने भाजपा कोर कमेटी और समन्वय समिति की बैठक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में की। बैठक का संचालन जिला महामंत्री संदीप सिंह एवं आभार विजय त्रिपाठी ने व्यक्त किया। इस अवसर पर आनंद द्विवेदी, आशीष सिंह रानू, विजय सिंह रघुवंशी, आलोक आर्य, अयोध्या प्रसाद वर्मा, रामेंद्र सिंह राणा, प्रदीप शुक्ल, राजेश सिंह, अरुण जायसवाल, मनोज श्रीवास्तव सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

देश का स्पोर्ट्स पावर हाउस बना हरियाणा : नायब सैनी

अब तक 17 हजार खिलाड़ियों को दिए 730 करोड़ के नकद पुरस्कार

चंडीगढ़ (हिंस)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा देश में स्पोर्ट्स का पावरहाउस बन गया है। हमारे प्रदेश की आबादी केवल देश की कुल आबादी की दो प्रतिशत है लेकिन जब भी ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेल या राष्ट्रमंडल खेलों की बात होती है तो हरियाणा के सबसे अधिक खिलाड़ी मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम ऊंचा करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुवार को नई दिल्ली के भारतमंडपम में आयोजित स्पोर्ट्स फिटनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपो में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह आयोजन केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि संकल्पों और सपनों का मेला है, जहां युवा शक्ति का सामर्थ्य साकार होता दिख रहा है। फिटनेस केवल व्यक्तिगत आदत नहीं बल्कि आज विकसित भारत की आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि इस कार्यक्रम में हरियाणा के पदकों की कहानी नहीं दिखेगी बल्कि हरियाणा का खेल मॉडल भी आप लोगों को दिखाई देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ओलंपिक, एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ तक नकद पुरस्कार दे रही है। पिछले 12 वर्षों में 17, 182 खिलाड़ियों को 730 करोड़ सीधे उनके खातों में हस्तांतरित किए गए हैं। 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को 1, 500 मासिक और 15 से 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2, 000 मासिक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा सरकार ने 260 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ग्रुप ए, बी व सी श्रेणी में सीधी सरकारी नौकरी दी है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बीते 12 वर्षों में लगभग 1100 करोड़ व्यय किए हैं। प्रदेशभर में करीब 2, 000 खेल नर्सरियां और 25 खेल अकादमियां संचालित, जहां प्रतिदिन 500 प्रति खिलाड़ी डाईट भत्ता दिया जा रहा है। पंचकूला में 10 करोड़ की लागत से उत्तर भारत के पहले अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है।

पीएनबी ने बचत खाताधारक के नॉमिनी को सौंपा 50 लाख का चेक

जोधपुर (हिंस)। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने रक्षक प्लस बचत खाता योजना के अंतर्गत रक्षक पेंशनभोगी खाताधारक के नॉमिनी को पचास लाख रुपए का चेक दिया। मंडल प्रमुख सचिन गतफने ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक अपनी पीएनबी रक्षक प्लस बचत खाता योजना के अंतर्गत सैनिक एवं पेंशनभोगी खाताधारकों को बिना किसी अतिरिक्त बीमा शुल्क के दुर्घटना बीमा प्रदान करता है। पीएनबी अपने रक्षक खाता धारक को एक करोड़ एवं रक्षक पेंशनभोगी खाता धारक को 50 लाख का मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना कवर देता है। हाल ही में एक भूतपूर्व सैनिक पेंशनभोगी खाता धारक स्वर्गीय सोहन सिंह पुत्र पाबूदान सिंह की एक दुर्घटना में दुखद रूप से मृत्यु हो गई थी। बैंक की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप पीड़ित की नॉमिनी पत्नी पुष्पा कंवर को उनके निवास जाकर पच्चास लाख रुपए की बीमित राशि का चेक सुपुर्द किया।

सोनीपत में महिला कांग्रेस ने कंगना रानौत के खिलाफ किया प्रदर्शन

सोनीपत (हिंस)। सोनीपत में अभिनेत्री कंगना रानौत के हालिया बयान तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी को लेकर लगाए गए आरोपों के विरोध में गुरुवार को महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कंगना रानौत और प्रहलाद जोशी के पुतले जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही महिला कांग्रेस नेत्री नीलम बाल्यान ने कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज कराया गया और प्रदर्शन के दौरान छात्राओं के साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना से महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। उन्होंने कंगना रनौत से छात्राओं और महिलाओं को लेकर की गई कथित टिप्पणी पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। नीलम बाल्यान ने अपने संबोधन में वर्ष दो हजार दो के गुजरात दंगों के दौरान हुए बिलकिस बानो प्रकरण का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि वर्ष दो हजार बाईस में दोषियों की रिहाई के मामले में भाजपा नेताओं का रवैया महिलाओं के सम्मान के अनुरूप नहीं था। उन्होंने प्रहलाद जोशी पर राजनीतिक आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं और छात्रों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रदर्शन में शामिल पायल मलिक ने कहा कि महिलाओं के सम्मान से जुड़े विषयों पर सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के साथ हुए व्यवहार पर भाजपा नेताओं ने चुप्पी साधे रखी। प्रदर्शन के अंत में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं के पुतले जलाए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

15 हजार की कमाई, लेकिन 6.79 करोड़ का टैक्स नोटिस! जूती कारीगर के खाते पर लगी रोक

बालोतरा (हिंस)। महीनेभर मेहनत करके मुश्किल से 10 से 15 हजार रुपए कमाने वाले एक साधारण जूती कारीगर के होश उस समय उड़ गए, जब उसके नाम पर 6 करोड़ 78 लाख 97 हजार 357 रुपए का जीएसटी बकाया निकल आया। तमिलनाडु से जारी इस नोटिस के बाद बैंक ने उसका खाता फ्रीज कर दिया। अब गरीब कारीगर न्याय की गुहार लगा रहा है और पूरे मामले में साइबर ठगी की आशंका जताई जा रही है। बालोतरा जिले के गुड़ामालानी के जीनगर मोहल्ला निवासी जितेंद्र कुमार जीनगर चमड़े की पारंपरिक जूतियां बनाकर परिवार का गुजारा करते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले मकान की पहली किस्त से एक कमरा बनवा रहे हैं। परिवार फिलहाल छोटे भाई के घर रह रहा है। ऐसे में करोड़ों रुपए के टैक्स नोटिस ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। जितेंद्र ने बताया कि 25 जुलाई को बैंक खाता बंद होने की जानकारी मिलने पर वह भारतीय स्टेट बैंक की गुड़ामालानी शाखा पहुंचे थे। बैंक अधिकारियों ने 28 जुलाई को आने को कहा। दोबारा पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि उनके नाम जीएसटी का भारी बकाया है और इसी कारण बैंक खाते पर रोक लगाई गई है। बैंक ने उन्हें तमिलनाडु से जारी नोटिस भी सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने गुड़ामालानी थाने में शिकायत दी, जहां से उन्हें साइबर थाना जाने की सलाह दी गई। जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु के वाणिज्यिक कर विभाग के कृष्णगिरी-2 असेसमेंट सर्किल की ओर से 5 मई 2026 को जारी नोटिस में *श्री शिवम एक्सपोर्ट्स* नामक फर्म पर वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक का करीब 6.79 करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया बताया गया है। इसी आधार पर पैन नंबर से जुड़े बैंक खातों, एफडी और अन्य खातों को तत्काल फ्रीज करने के निर्देश जारी किए गए। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी साइबर ठग गिरोह ने जितेंद्र के पैन कार्ड और पहचान संबंधी दस्तावेजों का दुरुपयोग कर तमिलनाडु के पते पर फर्जी कंपनी का पंजीकरण करा लिया। जितेंद्र का कहना है कि उन्होंने कभी कोई कंपनी नहीं बनाई और न ही तमिलनाडु से उनका कोई संबंध है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में पिता के निधन के बाद आर्थिक जरूरत के चलते उन्होंने बाड़मेर की एक फाइनेंस कंपनी से ऋण लेने के लिए दस्तावेज दिए थे। उस समय सिबिल जांच के नाम पर मोबाइल पर आए ओटीपी भी साझा कराए गए थे। उन्हें आशंका है कि उसी दौरान उनके दस्तावेज का गलत इस्तेमाल किया गया। जितेंद्र बताते हैं कि उनके परिवार में पत्नी, बेटा, बेटी और मां हैं। दिन-रात मेहनत के बावजूद महीने में 10 से 15 हजार रुपए की ही आमदनी हो पाती है।

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर राजग उम्मीदवार के लिए कोई चुनौती नहीं : ललन सिंह

पटना (हिंस)। बिहार में मुंगेर से जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ललन सिंह बांकीपुर विधानसभा के मतदाता हैं। मतदान करने के बाद उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के जीत का दावा किया और कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के लिए प्रशांत किशोर कोई चुनौती नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर कोई चुनौती नहीं हैं। प्रशांत किशोर पिछले विधानसभा चुनाव में भी तीर मार रहे थे। इस बार भी उनके जीत की कोई संभावना और उम्मीद नहीं है। प्रशांत किशोर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। बिहार की धरती ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती है, जो हवाबाजी में विश्वास करता हो। दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि यह चुनाव भाजपा नहीं बल्कि पुलिस लड़ रही है।

आज से नगर निकाय कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू सफाई, पेयजल व अन्य शहरी सेवाओं पर पड़ सकता है असर

सुपौल (हिंस)। बिहार लोकल बॉडिज इम्प्लाइज फेडरेशन एवं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ (एक्टू) के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार 30 जुलाई से नगर परिषद सुपौल सहित राज्य के सभी नगर निकायों के दैनिक वेतनभोगी, संविदा, आउटसोर्सिंग एवं नियमित कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल की सूचना नगर परिषद सुपौल के कार्यपालक पदाधिकारी एवं मुख्य पार्षद को पूर्व में ही लिखित रूप से दे दी गई थी। संरक्षक मो अरशद आलम एवं कार्यकारी अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार यादव , सचिव राज कुमार यादव ने कहा कि सरकार के साथ कई दौर की वार्ता के बावजूद उनकी तीन सूत्री मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसके कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के समाधान के लिए लंबे समय से सरकार से मांग की जा रही थी। कई बार वार्ता और आश्वासन मिलने के बावजूद किसी भी प्रमुख मांग पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इससे नगर निकाय कर्मियों में व्यापक असंतोष है और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल ही अंतिम विकल्प बचा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में कार्यरत कर्मचारी शहरों की सफाई, पेयजल आपूर्ति, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, राजस्व संग्रहण, जनस्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यक नागरिक सेवाओं का संचालन करते हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारी वर्षों से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं और उन्हें सेवा सुरक्षा, नियमित वेतनमान तथा अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। संघर्ष मोर्चा ने अपनी तीन प्रमुख मांगों में सबसे पहले वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, संविदा एवं अन्य अस्थायी कर्मियों के नियमितीकरण तथा सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग रखी है। कर्मचारियों का कहना है कि वे केवल सफाई कार्य ही नहीं, बल्कि अतिक्रमण हटाने, राजस्व वसूली, कार्यालयी कार्यों तथा विभिन्न सरकारी अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। दूसरी प्रमुख मांग नगर निकायों में लागू ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने की है। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि इस व्यवस्था के कारण श्रमिकों का आर्थिक शोषण होता है तथा बिचौलिया व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने मांग की है कि जब तक आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त नहीं होती, तब तक कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाए और समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाए। साथ ही एजेंसियों द्वारा की जाने वाली अवैध कटौती पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। तीसरी मांग नगर निकाय कर्मचारियों को एसीपी एवं एमएसीपी योजना का लाभ देने तथा बकाया राशि के भुगतान से संबंधित है। कर्मचारियों का कहना है कि अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह उन्हें भी समयबद्ध वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलना चाहिए, ताकि वर्षों से पदोन्नति से वंचित कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सके। हड़ताल से पहले 29 जुलाई को राज्यभर के नगर निकाय मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। अब हड़ताल की अवधि में कर्मचारी नगर निकाय मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन, सभा और जनजागरण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

बिना स्वीकृत पद पर पदस्थापन अनुचित, वन विभाग को नोटिस

जोधपुर (हिंस)। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जोधपुर ने बिना स्वीकृत पद पर किए गए वन विभाग के एक स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले के अनुसार, जैसलमेर में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर कार्यरत वसनाराम का प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा 10 जुलाई 2026 को उप वन संरक्षक (वन्यजीव) जैसलमेर से उप वन संरक्षक कार्यालय, नागौर में स्थानांतरण कर दिया गया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए वसनाराम ने अधिकरण में अपील दायर की। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा ने अधिकरण के समक्ष तर्क दिया कि उप वन संरक्षक, नागौर कार्यालय में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम का कोई स्वीकृत पद ही नहीं है। वर्ष 2015 में वन विभाग द्वारा स्वीकृत पदों की सूची के अनुसार वहां केवल क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय का पद स्वीकृत है। ऐसे में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर कार्यरत कर्मचारी का वहां पदस्थापन नियमों के विपरीत है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि प्रार्थी की नियुक्ति और वर्तमान सेवा क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर ही है। इसके बावजूद बिना पद सृजित हुए कार्यालय में स्थानांतरण करना विधि विरुद्ध और अनुचित है। अपील में यह भी बताया गया कि प्रार्थी का वर्तमान पदस्थापन 12 मई 2025 को हुआ था। जबकि वन विभाग की स्थानांतरण नीति के अनुसार किसी भी कर्मचारी का एक पद पर न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित है। इसके बावजूद लगभग एक वर्ष बाद ही स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया गया, जो विभागीय नीति के भी विपरीत है। सुनवाई के बाद राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने 10 जुलाई 2026 के स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी तथा वन विभाग को नोटिस जारी कर मामले में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

हर घर तिरंगा अभियान 2026 में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं तैयार करेंगी 2 करोड़ तिरंगे

लखनऊ (हिंस)। उत्तर प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे *हर घर तिरंगा अभियान-2026* को जनभागीदारी, राष्ट्रप्रेम और महिला सशक्तिकरण के उत्सव के रूप में व्यापक स्तर पर सफल बनाने की तैयारियां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दिशा-निर्देशन में तेज कर दी गई हैं। अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित 2 करोड़ तिरंगों का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रारंभ हुआ *हर घर तिरंगा अभियान* आज जन-जन के मन में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को और अधिक सशक्त करने वाला जनआंदोलन बन चुका है। यह अभियान देश की एकता, अखंडता और गौरवशाली राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं केवल तिरंगे का निर्माण ही नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने श्रम, कौशल और आत्मविश्वास के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित भारत के संकल्प को भी साकार कर रही हैं। ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित तिरंगा उनके आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी का भी प्रतीक बनेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। *हर घर तिरंगा अभियान-2026* महिलाओं के लिए रोजगार एवं आय के नए अवसर सृजित करने के साथ-साथ उनके उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि तिरंगों का निर्माण भारतीय ध्वज संहिता के निर्धारित मानकों के अनुरूप हो तथा स्वयं सहायता समूहों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भुगतान प्राप्त हो। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक अरुण कुमार ने बताया कि सहायता समूहों द्वारा निर्मित तिरंगों की गुणवत्ता, भारतीय ध्वज संहिता के मानकों का अनुपालन, समयबद्ध आपूर्ति तथा समूहों को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। अभियान के प्रभावी संचालन और सतत निगरानी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति में मुख्य विकास अधिकारी, उपायुक्त स्वत: रोजगार तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित दो अन्य सदस्य शामिल होंगे। जनपदों में तिरंगा निर्माण के लिए दैनिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रतिदिन निर्मित तिरंगों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी, ताकि जनपदवार निर्धारित लक्ष्य समय से पूर्ण किए जा सकें। तिरंगा निर्माण का कार्य अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराया जाएगा। तिरंगों का निर्माण भारतीय ध्वज संहिता के निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाएगा। झंडा आयताकार तथा 3-2 के अनुपात में होगा। इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग का निर्धारित मानकों के अनुसार प्रयोग किया जाएगा तथा सफेद पट्टी के मध्य 24 तीलियों वाला अशोक चक्र अंकित किया जाएगा। तिरंगा खादी, हाथ से कते अथवा मशीन से बने सूती, पॉलिएस्टर, ऊनी अथवा सिल्क जैसे अनुमन्य कपड़ों से तैयार किया जाएगा।

राजस्थानी भाषा को अनिवार्य विषय व राजभाषा घोषित करने की मांग

जोधपुर (हिंस)। राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर संघर्षरत संस्था राजस्थानी मोट्यार परिषद की ओर से आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्राधिकरण के राज्य मंत्री ओंकार सिंह लखावत को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राजस्थान के सभी विद्यालयों में राजस्थानी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने, रीट सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थानी भाषा को शामिल करने तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत राजस्थानी भाषा को राजस्थान की राजभाषा घोषित करने की मांग की गई। परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश मेघवाल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय की भावना के अनुरूप राज्य सरकार को शीघ्र प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। साथ ही, राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी पहल करने का भी आग्रह किया गया। परिषद ने कहा कि राजस्थानी भाषा राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और जनभावनाओं की आत्मा है। वर्ष 2003 में राजस्थान विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के बावजूद आज तक राजस्थानी भाषा को अपेक्षित संवैधानिक एवं प्रशासनिक सम्मान नहीं मिल पाया है। अब समय आ गया है कि राज्य सरकार इस दिशा में ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए। परिषद ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए राजस्थानी भाषा के संरक्षण, संवर्धन तथा संवैधानिक सम्मान के लिए आवश्यक निर्णय लेंगे।

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला जुनिपर ग्रीन एनर्जी का आईपीओ, 6 अगस्त को हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली

रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जुनिपर ग्रीन एनर्जी का 1,800 करोड़ रुपये का पब्लिक इश्यू (आईपीओ) सब्सक्रिप्शन के लिए लान्च कर दिया गया। इस आईपीओ में निवेशक तीन अगस्त तक बोली लगा सकेंगे। क्लोजिंग के बाद चार अगस्त को शेयरों का अलाटमेंट किया जाएगा, जबकि पांच अगस्त को अलाटेड शेयर डिमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर छह अगस्त को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं।

इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 214 रुपये से लेकर 225 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लाट साइज 66 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स कम से कम 1 लाट यानी 66 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 14,850 रुपये का निवेश करना होगा। इसी तरह रिटेल इनवेस्टर 1,93,050 रुपये के निवेश से अधिकतम 13 लाट में 858 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 1,800 करोड़ रुपये के कुल 8,00,09,150 नए शेयर जारी हो रहे हैं।

इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 49.94 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 34.96 प्रतिशत हिस्सा और नान इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 14.98 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों के लिए 0.12 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस इश्यू के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है। वहीं केफिन टेक्नोलाजीज लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है।

जुनिपर ग्रीन एनर्जी की वित्तीय स्थिति की बात करें, तो प्रास्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत मामूली उतार चढ़ाव के बावजूद मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 40.06 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में घटकर 36.48 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 40.46 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में लगातार बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में इसे 424.45 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 569.78 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 804.93 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

न्यूज ब्रीफ

रणनीतिक बढ़त के लिए भारत को त्वरित सुधारों की दरकार: वित्त मंत्रालय, वैश्विक चुनौतियों और बदलते हालात के मद्देनजर आंतरिक सुधार पर जोर

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक रिपोर्ट में कहा है कि रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए भारत को खुद को नए सिरे से ढालना होगा और वैश्विक जरूरतों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं पर नए दृष्टिकोण से सोचना होगा। मंत्रालय ने बढ़ते बाहरी हालात के बीच घरेलू सुधार, समझदारी भरे वृहद आर्थिक प्रबंधन और त्वरित नीतिगत प्रतिक्रिया को महत्वपूर्ण बताया। यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रक्रियाओं में सुधार और संस्थागत दक्षता मजबूत करने पर जोर देने के एक दिन बाद आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल ही में प्रक्रियाओं में सुधार और संस्थागत दक्षता मजबूत करने पर जोर दिया था। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से जोड़ते हुए नवाचार, विविधीकरण और क्षमता बढ़ाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का आह्वान किया। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत घरेलू आधार, लगातार नीतिगत समर्थन और संरचनात्मक कारकों की वजह से मजबूत बनी हुई है। हालांकि, खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव से महंगाई, राजकोषीय घाटे और वृद्धि दर के नरम पड़ने का जोखिम बना हुआ है। आर्टिफिशाल इंटेलिजेंस और आपूर्ति श्रृंखला के हथियार बनने जैसी वैश्विक घटनाओं के मद्देनजर मंत्रालय ने विदेशी और घरेलू निवेश हेतु त्वरित नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन पर बल दिया।

आकलन वर्ष 2026-27 के लिए 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल, 31 जुलाई है आखिरी तारीख

नई दिल्ली। आकलन वर्ष 2026-27 के लिए 5 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न (आईटीआर) पहले ही फाइल किए जा चुके हैं। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख (डेडलाइन) 31 जुलाई है। आयकर विभाग ने एक्स पर जारी पोस्ट में करदाताओं को सलाह दी है कि अंतिम तारीख आने से पहले सभी करदाता आईटीआर-1 और आईटीआर-2 जमा कर दें ताकि डेडलाइन के पास आने पर जल्दबाजी और अन्य तकनीकी व्यवधानों से बचा जा सके। विभाग ने कहा, आकलन वर्ष 2026-27 के लिए 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर पहले ही भरे जा चुके हैं। आखिरी समय की हड़बड़ी का इंतजार न करें। असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अपना आईटीआर-1 या आईटीआर-2 मिलान करें और फाइल करें। स्मार्ट तरीके से अपना आईटीआर फाइल करें। आयकर विभाग ने यह रिमाइंडर उन करदाताओं के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले दिया है, जिन्हें आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए अपने अकाउंट्स का आडिट कराने की जरूरत नहीं है।

एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर की दौड़ में भारत को बढ़त, अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर

नई दिल्ली। भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) नवाचार में अमेरिका और चीन का दबदबा कायम है,

लेकिन एआई माडल को प्रशिक्षित व संचालित करने के लिए आवश्यक फिजिकल कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की वैश्विक होड़ भारत के लिए आर्थिक रूप से बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। इस क्षेत्र में हो रहा भारी निवेश देश में स्वच्छ ऊर्जा, विनिर्माण, रियल एस्टेट और उच्च-स्तरीय सेवा जैसे कई सहायक क्षेत्रों को नई गति प्रदान कर रहा है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदाणी समूह जैसे भारतीय कारोबारी घरानों के साथ-साथ माइक्रोसाफ्ट, गूगल और एमेजान जैसी वैश्विक तकनीकी कंपनियों द्वारा स्थापित किए जा रहे एआई आधारित डेटा सेंटर अब केवल व्यक्तिगत परियोजनाएं न होकर, पूरी औद्योगिक मूल्य श्रृंखला को आकर्षित करने वाले प्रमुख केंद्र बन रहे हैं, जिससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। लोढ़ा डेवलपर्स जैसी रियल एस्टेट कंपनियां पावर्ड शेल्स (आईटी उपकरणों को छोड़कर सभी सुविधाओं से लैस इमारतें) जैसी यूटिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाकर तकनीकी कंपनियों को पट्टे पर दे रही हैं, जिससे उन्हें स्थिर आय मिल रही है।

धवल पैकेजिंग का आईपीओ लान्च, 3 अगस्त तक लगाई जा सकती है बोली

नई दिल्ली

प्लास्टिक पैकेजिंग साल्यूशंस का निर्माण करने वाली कंपनी धवल पैकेजिंग लिमिटेड का 36.36 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए लान्च कर दिया गया। इस आईपीओ में तीन अगस्त तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद चार अगस्त को शेयरों का अलाटमेंट किया जाएगा, जबकि पांच अगस्त को अलाटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर छह अगस्त को बीएसई के एसएमई प्लेटफार्म पर लिस्ट हो सकते हैं।

इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 92 रुपये से लेकर 97 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लाट साइज 1,200 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लाट यानी 2,400 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,32,800 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 37,48,800 नए शेयर जारी हो रहे हैं।

इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 45.84 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 32.14 प्रतिशत हिस्सा और नान इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 13.80 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इसके अलावा मार्केट मेकर के लिए 5.02 प्रतिशत हिस्सा और कंपनी के कर्मचारियों के लिए 3.20 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस इश्यू के लिए रेयरएवर फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि केफिन टेक्नोलाजीज लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। वहीं न्यू बेरी कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मार्केट मेकर है।

धवल पैकेजिंग की वित्तीय स्थिति की बात करें, तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 1.55 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 6.04 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 8.04 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में इसे 48.08 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 52.43 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 65.20 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस अवधि में कंपनी पर लदे कर्ज के बोझ में उतार-चढ़ाव होता रहा। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी पर 19.28 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में कम होकर 16.55 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें, तो इस दौरान कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ उछल कर 24.13 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

इस अवधि में कंपनी के नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 4.10 करोड़ रुपये के स्तर पर था। इसी तरह 2024-25 में कंपनी का नेटवर्थ बढ़ कर 20.16 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में ये 30.75 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। कंपनी के रिजर्व और सरप्लस की बात करें, तो इस अवधि में कंपनी इस मोर्चे पर भी बढ़त हासिल करने में सफल रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 2.10 करोड़ रुपये के स्तर पर था। इसी तरह 2024-25 में कंपनी का रिजर्व और सरप्लस जबरदस्त उछाल के साथ 17.75 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का रिजर्व और सरप्लस 20.76 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

इसी तरह ईबीआईटीडीए (अनिंग बिफोर इंट्रेस्ट, टैक्सेज, डिप्रेशिएशंस एंड एमार्टाइजेशन) 2023-24 में 4.99 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2024-25 में बढ़ कर 10.22 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का ईबीआईटीडीए उछल कर 13.93 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

एथनाल के डर से हाई आक्टेन पेट्रोल की बिक्री दोगुनी से ज्यादा बढ़ी

नई दिल्ली

जुलाई में विवाद बढ़ने से मांग में तेजी, अधिकारी बोले, यह उछाल अस्थायी

एथनाल मिश्रित पेट्रोल से गाड़ियों को संभावित नुकसान पहुंचने की बढ़ती चिंताओं के बीच हाल के महीनों में एथनाल-मुक्त 100-आक्टेन प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। यह उछाल जुलाई माह में खास तौर पर ज्यादा देखा गया, जब पेट्रोल में एथनाल मिश्रण को लेकर विवाद अपने चरम पर था, जिसने उपभोक्ताओं की चिंताएं बढ़ा दीं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियां इंडियन आयल (एक्सपी100), भारत पेट्रोलियम (स्पीड100) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (पावर100) ब्रांड के तहत यह उच्च-आक्टेन ईंधन बेचती हैं। यह विशेष रूप से सुपरकार, लक्जरी सिडैन और सुपरबाइक जैसी उच्च-प्रदर्शन वाली गाड़ियों के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि, देश की कुल पेट्रोल बिक्री में इसकी हिस्सेदारी महज 0.1 प्रतिशत है, लेकिन सोशल मीडिया पर एथनाल मिश्रित पेट्रोल से वाहनों को नुकसान पहुंचने के दावों ने इसकी मांग में अचानक वृद्धि कर दी है। सूत्रों के अनुसार एथनाल-मुक्त पेट्रोल की इस बढ़ी हुई मांग का सबसे ज्यादा असर दिल्ली में देखा गया है। राष्ट्रीय राजधानी में 100-आक्टेन प्रीमियम पेट्रोल की कीमत लगभग 160 रुपये प्रति लीटर है, जो सामान्य पेट्रोल (20 फीसदी एथनाल मिश्रित, 102.12 रुपए लीटर) से लगभग 57 फीसदी महंगा है। यहां तक कि ई20-मिश्रित प्रीमियम ग्रेड (जैसे एक्सपी 95) भी 111-112 रुपए प्रति लीटर में बिकता है। कम मांग के चलते, देश के 1 फीसदी से भी कम पेट्रोल पंपों पर 100-आक्टेन पेट्रोल उपलब्ध है और यह ज्यादातर बड़े शहरों तक ही सीमित है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि एथनाल-मुक्त प्रीमियम पेट्रोल की मांग में यह हालिया उछाल संभवत: अस्थायी है। उनका कहना है कि एथनाल मिश्रित ईंधन को लेकर चिंताएं कम होने पर बिक्री सामान्य हो जाएगी, क्योंकि यह ईंधन सुपर-प्रीमियम गाड़ियों के लिए है। सामान्य वाहनों के लिए इसकी उच्च लागत लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होगी, जिससे वाहन मालिक का ईंधन बजट काफी बढ़ सकता है।

कच्चे तेल में फिर गिरावट, तनाव के बीच भी आपूर्ति बरकरार

नई दिल्ली। पिछले कारोबारी दिन की जोरदार उछाल के बाद कच्चे तेल की कीमतों में फिर गिरावट दर्ज की गई। इसकी मुख्य वजह यह रही कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद, बाजार को यह विश्वास है कि तेल की वैश्विक आपूर्ति पूरी तरह से बाधित नहीं हुई है। ताजा कारोबार में ब्रेंट क्रूड करीब 1.3 फीसदी गिरकर 86.94 डालर प्रति बैरल पर और डब्ल्यूटीआई क्रूड करीब 1.4 फीसदी टूटकर 83.30 डालर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा। बीते कुछ दिनों से कच्चे तेल के दामों में काफी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। बुधवार को जहां कीमतों में जोरदार उछाल आया था, वहीं मंगलवार को भी इनमें गिरावट दर्ज हुई थी। मौजूदा गिरावट का सबसे बड़ा कारण यही है कि लाल सागर जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों से तेल और मालवाहक जहाजों की आवाजाही लगातार जारी है। रिपोर्टों के अनुसार, मंगलवार को बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य से 39 मालवाहक जहाज गुजरे, जो हाल के दिनों में सबसे अधिक संख्या है, जिससे बाजार की चिंताएं कुछ कम हुई हैं। हालांकि, पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव कम नहीं हुआ है।

सर्राफा बाजार में सोने के भाव में गिरावट जारी, चांदी की कीमत में बदलाव नहीं

नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान सोने की कीमत में गिरावट का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। हालांकि चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कीमत में आई कमजोरी के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना 600 रुपये प्रति 10 ग्राम लेकर 660 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है।

कीमत में हुए बदलाव के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,43,500 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,43,650 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,31,540 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,31,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में बदलाव नहीं होने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में भी 2,34,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,43,650 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,31,690 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,43,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,31,540 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,43,550 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,31,590 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,43,500 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,31,540 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,43,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,31,540 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,550 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,31,590 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,43,650 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,31,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,550 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,31,590 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत, एशिया में मिला-जुला कारोबार

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं डाउ जान्स फ्यूचर्स बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान मिला-जुला कारोबार होता रहा। वहीं एशियाई बाजार में भी मिला-जुला कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसले से स्टाक मार्केट और अमेरिकी बान्ड मार्केट का मूड बिगड़ गया, जिसकी वजह से वाल स्ट्रीट के सूचकांक बड़ी गिरावट का शिकार हो गए। रेगुलर ट्रेडिंग सेशन में डाउ जान्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1,153.18 अंक यानी 2.19 प्रतिशत टूट गया। इसी तरह एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 112.63 अंक यानी 1.52 प्रतिशत लुढ़क कर 7,316.15 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डेक

433.97 अंक यानी 1.74 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,442.94 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं डाउ जान्स फ्यूचर्स फिलहाल 0.13 प्रतिशत की मजबूती के साथ 51,660.39 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के बाद मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। एफटीएसई इंडेक्स 0.34 प्रतिशत की तेजी के साथ 10,908.41 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसके विपरीत सीएसी इंडेक्स ने 0.60 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 8,408.27 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 0.01 प्रतिशत की सांकेतिक गिरावट के साथ 25,460.48 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार हो रहा है। एशिया के नौ बाजार में से पांच के सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि चार सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में बने हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी 0.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,315.50 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह निक्केई इंडेक्स 300.81 अंक यानी 0.49 प्रतिशत की तेजी के साथ 61,735 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा ताईवान वेटेड इंडेक्स 489.57 अंक यानी 1.22 प्रतिशत की छलांग लगा कर 40,528.75 अंक के स्तर पर और जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 0.84 प्रतिशत की मजबूती के साथ 6,142.38 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

दूसरी ओर, स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.77 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 5,669.14 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसी तरह हैंग सेंग इंडेक्स 0.07 प्रतिशत टूट कर 25,789 अंक के स्तर पर आ गया है। कोस्पी इंडेक्स में बड़ी गिरावट नजर आ रही है। फिलहाल यह सूचकांक 99.34 अंक यानी 1.75 प्रतिशत फिसल कर 5,563.90 अंक के स्तर पर आ गया है। सेट कंपोजिट इंडेक्स में भी 1.56 प्रतिशत की कमजोरी नजर आ रही है। फिलहाल यह सूचकांक 1,599.18 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.15 प्रतिशत लुढ़क कर 3,784.55 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

रैना बोले, अनुशासन, कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से अच्छा फील्डर बना

नई दिल्ली

पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना अपनी बल्लेबाजी के साथ ही बेहतरीन फील्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं। रैना के अनुसार अनुशासन, कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से ही वह एक एक बेहतर फील्डिर बने थे। रैना का मानना है कि लगातार अभ्यास की एक मजबूत संस्कृति भारतीय क्रिकेट में हैं जिससे सभी को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए निर्धारित समय से आधा घंटा पहले मैदान पर पहुंच जाते थे, क्योंकि उनके सत्र की शुरुआत हमेशा फील्डिंग से होती थी। यह आज की तरह मात्र कुछ कैच पकड़कर समाप्त होने वाला सत्र नहीं था, बल्कि इसमें हाई कैच, ग्राउंड फील्डिंग, स्लिप कैच और पैरेलल कैच जैसे विभिन्न अभ्यास शामिल होते थे। वह उत्तर प्रदेश में मोहम्मद कैफ के नेतृत्व को याद करते हैं, जो एक स्टंप लगाकर सीधे उस पर थ्रो करने का अभ्यास कराते थे और कहते थे, अगर सीधे स्टंप पर थ्रो नहीं मारोगे, तो अंतिम ग्यारह में जगह नहीं मिलेगी। इन्हीं कठिन और सटीक अभ्यास सत्रों ने उनकी फील्डिंग को मजबूत आधार दिया।

रैना की फील्डिंग को बेहतर बनाने में आदर्श खिलाड़ियों की टिप्स की भी अहम भूमिका रही। उन्होंने कहा कि जोंटी रोड्स जैसे महान फील्डर से तारीफ मिलना हमेशा खास होता है, क्योंकि वह हमेशा उनके आदर्श रहे हैं। भारत में उन्हें मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह से काफी प्रेरणा मिली। युवराज सिंह पाइंट और कवर पर फील्डिंग करते थे, जबकि रैना मिड-आफ पर तैनात रहते थे। उनका लक्ष्य रहता था कि गेंद उनके बीच से न निकल पाए, जिससे भारतीय टीम के लिए एक मजबूत मध्य-फील्डिंग साझेदारी बनी। रैना ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की एक डरावनी घटना को भी साझा किया, जो आस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी में इरफान पठान के साथ हुई थी। रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे और डेविड वार्नर ने स्वीप शाट खेला, जिसमें गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में उछल गई। रैना मिडविकेट पर थे और इरफान कैच पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे रैना ने बताया, मैं सिर्फ गेंद को देख रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इरफान कहां हैं। मुझे सिर्फ गेंद, फ्लडलाइट्स, दर्शक और पीछे लहराता तिरंगा दिखाई दे रहा था। जैसे ही उन्होंने कैच पूरा किया, उनकी जोरदार टक्कर इरफान पठान से हो गई। रैना ने कहा कि एक पल के लिए उन्हें लगा कि अगर उनका सिर इरफान के शरीर से टकराता तो गंभीर चोट लग सकती थी, लेकिन शुक्र है कि सिर्फ उनका कंधा टकराया और वे कैच पकड़ने में सफल रहे। हालांकि, इस टक्कर में इरफान पठान की पसली में फ्रैक्चर हो गया था और उन्हें काफी चोट आई। इस घटना से हमने एक बड़ी सीख ली कि जिसका कैच हो, उसे जोर से आवाज लगाकर बताना चाहिए। इस घटना ने फील्डरों के बीच बेहतर संवाद की अहमियत को उनके मन में हमेशा के लिए बिठा दिया रैना ने निष्कर्ष निकाला कि शुरुआती वर्षों में मिला कठिन प्रशिक्षण, अनुभवी साथियों से मिली सीख और मैदान पर हुए ऐसे अनुभवों ने ही उन्हें एक ऐसा फील्डर बनाया, जिसकी फुर्ती, पूर्वानुमान क्षमता और समर्पण की लंबे समय तक प्रशंसा होती रही।

न्यूज ब्रीफ

भारतीय मूल के जय आयरलैंड से एकदिवसीय खेलते दिखेंगे

मुम्बई। भारतीय मूल के राजस्थान में जन्मे क्रिकेटर जय मूंदड़ा अब आयरलैंड क्रिकेट टीम से खेलते नजर आयेंगे। जय को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए आयरलैंड की एकदिवसीय टीम में शामिल किया गया है। जय का जन्म राजस्थान में हुआ था पर पढ़ाई के लिए वह आयरलैंड चले गए थे। जय का सपना क्रिकेटर बनना था जो अब पूरा होता दिख रहा है। कुछ समय पहले ही जय ने आयरलैंड की ओर से टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में ही शानदार प्रदर्शन कर दो मैचों में 5 विकेट लिए थे, जिससे आयरलैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में जीत हासिली की थी। इस प्रदर्शन के बल पर अब उन्हें एकदिवसीय टीम में जगह मिली है। यदि जय अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में अपना वनडे डेब्यू करते हैं, तो वह आयरलैंड के लिए एकदिवसीय खेलने वाले दूसरे भारतीय मूल के क्रिकेटर बन जाएंगे। आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच 5 से 14 अगस्त के बीच पांच मुकाबलों की एकदिवसीय सीरीज खेली जाएगी। इसके शुरुआती तीन मुकाबलों के लिए आयरलैंड ने अपनी 14 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। इस सीरीज में कप्तान पाल स्टर्लिंग भी वापसी कर रहे हैं, जो पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान लगी चोट से उबर चुके हैं। जय मूंदड़ा के अलावा, बेन कैलिट्ज और बायरन मैकडोनो को भी उनके हालिया शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार एकदिवसीय टीम में शामिल किया गया है। कैलिट्ज भी जय मूंदड़ा के साथ भारत के खिलाफ ऐतिहासिक टी20 सीरीज जीत का हिस्सा थे। हालांकि, चोटों के कारण आयरलैंड को इस सीरीज में कई अनुभवी खिलाड़ियों के बिना मैदान पर उतरना होगा। तेज गेंदबाज जोश लिटिल, मैट हालैंड, क्रेग यंग, बैरी मैकार्थी, जार्डन नील और डेविड डेलानी जैसे प्रमुख खिलाड़ी चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे, जिससे टीम को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पांच मुकाबलों की यह एकदिवसीय सीरीज 5 अगस्त को ब्रेडी में शुरू होगी, जहां 7 अगस्त को दूसरा मैच भी खेला जाएगा। शेष तीन मुकाबले 10, 12 और 15 अगस्त को स्टार्मोंट में खेले जाएंगे। यह सीरीज नए नियुक्त हेड कोच गैरी विल्सन के लिए भी पहला महत्वपूर्ण असाइनमेंट होगी।

आशुतोष के नाम है घरेलू क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकार्ड

मुम्बई। टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक की बात करे तो अधिकतर प्रशंसकों की नजरें आक्रामक आलराउंडर युवराज सिंह की ओर जाती हैं पर ये सही नहीं घरेलू क्रिकेट में ये रिकार्ड युवराज नहीं बल्कि मध्यप्रदेश के बल्लेबाज आशुतोष शर्मा के नाम है। आशुतोष ने साल 2023 को सैयद मुश्ताक अली ट्राफी में रेलवे की ओर से खेलते हुए यह ऐतिहासिक रिकार्ड अपने नाम किया था। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मुकाबले में आशुतोष ने केवल 11 गेंदों में अर्धशतक लगा दिया जबकि युवराज ने 12 गेंदों में ये कारनामा किया था। इस के साथ ही आशुतोष भारत के लिए सबसे तेज टी20 अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए थे। इस पारी के दौरान आशुतोष ने मैदान के चारों ओर चौकों और छक्के लगाये जिससे विरोधी गेंदबाजों को कोई अवसर नहीं मिला। उनकी इस विस्फोटक पारी से रेलवे ने एक विशाल स्कोर बनाया। उनकी यह पारी टी20 फार्मेट की तेजी और अनिश्चितता का बेहतरीन उदाहरण है, जहां कोई भी बल्लेबाज किसी भी पल मैच का रुख पलट सकता है।

एशेज में वापसी कर सकते हैं स्टोक्सः मैकडोनाल्ड

मेलबर्न। आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने दावा किया है कि हाल में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले इंग्लैंड के आलराउंडर बेन स्टोक्स अगले साल होने वाली एशेज सीरीज में वापसी कर सकते हैं। स्टोक्स ने पिछले महीने न्यूजीलैंड से सीरीज हारने के बाद अचानक ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उनके टीम में नहीं रहने से इंग्लैंड को करारा झटका लगा है। मैकडोनाल्ड ने हालांकि कहा कि कि उनके पास स्टोक्स के अंतरराष्ट्रीय भविष्य को लेकर कोई पक्की जानकारी नहीं है पर उनका आंकलन है कि इंग्लैंड प्रबंधन इस पूर्व कप्तान को वापसी के लिए मनाएगा। इसलिए अगर स्टोक्स एशेज 2027 के लिए वापसी करते हैं तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। आस्ट्रेलियाई कोच ने कहा, अगर वह संन्यास से वापसी करें और एक और एशेज खेलें, तो यह अच्छा रहेगा। उसकी वापसी काफी चर्चाओं में रहेगी। उन्होंने साथ ही कहा, अगर आप उस सीरीज रोमांच बनाना चाहते हैं, तो शायद आप यही चाहेंगे कि वह संन्यास से वापसी करें। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं होगा जब स्टोक्स ने संन्यास से वापसी की हो। 2022 में, वह इंग्लैंड के लिए 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप खेलने के लिए एकदिवसीय से वापस लौटे थे पर टीम अपना खिताब बचाने में असफल रही थी। स्टोक्स अभी इंग्लैंड की घरेलू 50-ओवर प्रतियोगिता में डरहम के लिए खेल रहे हैं, जहां उन्होंने लगातार नाबाद 108 और 73 रन की प्रभावशाली पारियां खेली हैं।

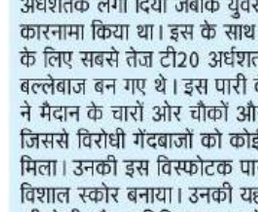

वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्राफी मे ईस्ट जोन के उप-कप्तान बने : ईशान किशन को कप्तानी, मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार भी टीम में

नई दिल्ली

दलीप ट्राफी 2026-27 के लिए ईस्ट जोन की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। ईशान किशन को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को उप-कप्तान बनाया गया है। टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार भी शामिल हैं। वहीं, चोट के कारण रियान पराग और आकाश दीप का चयन नहीं हुआ। दलीप ट्राफी 23 अगस्त से खेली जाएगी। टी-20 से दलीप ट्राफी तक वैभव का सफर वैभव सूर्यवंशी ने इसी महीने इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था। इसके बाद जिम्बाब्वे दौरे पर तीसरे टी-20 में 49 गेंदों पर 81 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर आफ द मैच और पूरी सीरीज में 181 रन बनाने के लिए प्लेयर आफ द सीरीज चुना गया।

इससे पहले इसी साल जिम्बाब्वे में खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 175 रन बनाकर भारत को चैंपियन बनाया था। कम उम्र में ही वैभव ने बड़े मुकाबलों में खुद को साबित किया है। IPL 2026 के एलिमिनेटर में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रन और क्वालिफायर-2 में राजस्थान रायल्स के खिलाफ 96 रन की अहम पारियां खेलीं। पिछले महीने श्रीलंका में इंडिया-ए की ओर से ट्राई सीरीज के फाइनल में भी उन्होंने 94 रन बनाए थे। वैभव ने अब तक आठ फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। इसमें 17.25 की औसत से 207 रन बनाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 93 रन है। उन्होंने अपना पिछला फर्स्ट क्लास मुकाबला पिछले साल बिहार की ओर से मेघालय के खिलाफ रणजी प्लेट लीग में खेला था।

ईश्वरन के साथ कर सकते हैं ओपनिंग - टीम में वैभव के साथ बंगाल के अनुभवी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन पारी की शुरुआत कर सकते हैं। 113 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके ईश्वरन टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं और घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं। झारखंड के शिखर मोहन को रिजर्व ओपनर के तौर पर शामिल किया गया है।

शमी बालिंग अटैक लीड करेंगे - मोहम्मद शमी ईस्ट जोन के तेज गेंदबाजी की अगुआई करेंगे। उनके साथ मुकेश कुमार और सूरज सिंधु जायसवाल नई गेंद संभालेंगे। स्पिन आलराउंडर शाहबाज अहमद भी टीम का हिस्सा हैं। त्रिपुरा के अभिजीत सरकार 15 सदस्यीय टीम में चुने जाने वाले अपने राज्य के इकलौते खिलाड़ी हैं।

झारखंड के खिलाड़ियों का दबदबा - ईस्ट जोन की टीम में ईशान किशन विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे। उनके अलावा कुमार कुशाग्र दूसरे विकेटकीपर हैं। झारखंड के विराट सिंह, अनुकूल राय और शिखर मोहन को भी टीम में जगह मिली है। अनुकूल राय हाल ही में श्रीलंका में ट्राई सीरीज जीतने वाली इंडिया-ए टीम का हिस्सा रहे थे।

ईस्ट जोन की पूरी टीम - ईशान किशन (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उप-कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, सुदीप कुमार घरामी, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, शाहबाज अहमद, सूरज सिंधु जायसवाल, विराट सिंह, कुमार कुशाग्र, शिखर मोहन, सुभ्रांशु सेनापति, अभिजीत सरकार, अनुकूल राय और डेनिश दास।

बुमराह अपनी फिटनेस बनाये रखने के लिए स्वयं उपाय करें : मैक्ग्रा

मुम्बई

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी फिटनेस को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। उनके लगातार चोटिल होने का खतरा बना रहता है जिससे भारतीय टीम को भी नुकसान होता है। श्रीलंका के खिलाफ अगले माह होने वाली टेस्ट सीरीज में भी उनका खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा। वहीं पूर्व आस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा ने कहा है कि बुमराह को अपना ध्यान स्वयं रखना होगा। मैक्ग्रा ने कहा कि बुमराह को अपनी फिटनेस बनाये रखने और अपने करियर को लंबा करने का तरीका स्वयं तलाशना होगा।

मैक्ग्रा ने कहा, यह बुमराह पर ही निर्भर करता है कि वे क्या चाहते हैं। वे अभी युवा हैं, इसलिए उन्हें अपनी पारी को लंबा खींचने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मैक्ग्रा ने बुमराह की चोटों का जिक्र करते हुए उन्हें एक बेहतरीन गेंदबाज बताया। उन्होंने कहा कि बुमराह को यह तय करना होगा कि वे टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या सिर्फ टी20 खेलना चाहते हैं। यह उनके शरीर और गेंदबाजी एक्शन पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि जो गेंदबाज अपनी बांह को अधिक खींचते हैं, वे उस जोड़ पर थोड़ा ज्यादा दबाव डालते हैं।

मैक्ग्रा ने सभी तेज गेंदबाजों से आग्रह किया कि वे बार-बार होने वाली चोटों से बचने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने के बजाय तेज गेंदबाजी से जुड़े तनाव को स्वीकार करना सीखें। उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि आजकल तेज गेंदबाजों को बहुत ज्यादा सुरक्षा दी जाती है। मैक्ग्रा ने समझाया, तेज गेंदबाज होना खेल की प्रकृति है। यह स्वाभाविक क्रिया नहीं है, इसलिए चोटें खेल का हिस्सा हैं। उन्होंने आगे कहा कि तेज गेंदबाजों को बहुत ज्यादा सुरक्षित रखने के बजाय, उन्हें तेज गेंदबाजी के दबाव से भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए। उनका मानना है कि महीनों तक रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम करने से फिटनेस और ताकत कम हो जाती है, जिसकी भरपाई में लंबा समय लगता है।

मैक्ग्रा ने बताया कि 1993 से 2007 तक के अपने लंबे टेस्ट करियर के शुरुआती दौर में उन्हें कमर की गंभीर चोट लगी थी। उन्होंने कहा, जब मेरी कमर की मांसपेशी फट गई, तब मेरा वजन बहुत कम था। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं यही करता रहा, तो मैं ज्यादा समय तक नहीं टिक पाऊंगा। इसके बाद उन्होंने केविन शेवेल के साथ काम किया, जिन्होंने उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनने में मदद की।

भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी को हराया, नाओरेम सोमनंदा सिंह का शानदार गोल

रांची। नाओरेम सोमनंदा सिंह के शानदार गोल और दूसरे हाफ में डिफेंडर्स एफसी के आत्मघाती गोल की मदद से भारतीय वायुसेना फुटबाल टीम ने 135वें डूरंड कप के ग्रुप सी मुकाबले में श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी को 2-1 से हराया। बिरसा मुंडा फुटबाल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय वायुसेना के लिए नाओरेम ने 25वें मिनट में गोल किया, जबकि 68वें मिनट में डिफेंडर्स एफसी के के. डी. एस. संकल्पा ने गलती से गेंद अपने ही गोल में डाल दी। डिफेंडर्स की ओर से एन. एम. अफलाल ने 70वें मिनट में गोल किया। शुरुआत से ही दिखाया आक्रामक खेल भारतीय वायुसेना ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और श्रीलंकाई टीम को लगातार दबाव में रखा। 25वें मिनट में डिफेंडर्स एफसी के डिफेंडर संपत कुमार की गलती का फायदा उठाते हुए नाओरेम ने बाक्स के बाहर से शानदार दाएं पैर का शाट लगाकर टीम को बढ़त दिलाई। यह टूर्नामेंट में उनका तीसरा गोल था। दूसरे हाफ में भी भारतीय वायुसेना का दबदबा कायम रहा। 68वें मिनट में बाएं छोर से आए खतरनाक क्रास को रोकने के प्रयास में संकल्पा ने गेंद अपने ही गोल में डाल दी और भारतीय टीम की बढ़त 2-0 हो गई। दो मिनट बाद हालांकि, अफलाल ने तेज जवाबी हमले पर गोल कर डिफेंडर्स की वापसी की उम्मीद जगाई। अंतिम क्षणों में डिफेंडर्स एफसी ने बराबरी के लिए जोर लगाया, लेकिन भारतीय वायुसेना ने संयम बनाए रखते हुए जीत हासिल की।

राष्ट्रमंडल खेल 2026 : दिलीप गावित ने जीता स्वर्ण, मोहम्मद बासिल को रजत

ग्लासगो

राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय पैरा एथलेटिक्स दल ने इतिहास रच दिया। दिलीप गावित और मोहम्मद बासिल ने पुरुषों की 100 मीटर टी47 स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीतकर भारत को ऐतिहासिक डबल पोडियम दिलाया।

दिलीप गावित ने 10.71 सेकेंड का समय निकालते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनका यह प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकार्ड भी बन गया। वहीं मोहम्मद बासिल ने 10.83 सेकेंड के साथ रजत पदक हासिल किया। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में अपना सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले भारोत्तोलन में मीराबाई चानू और पैरा शाटपुट में शर्मिला धनकर भारत को स्वर्ण पदक दिला चुकी हैं।

संघर्ष से शिखर तक दिलीप गावित का सफर - महाराष्ट्र के नासिक जिले के निकट स्थित छोटे से गांव तोरण डोंगरी में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे दिलीप गावित का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। बचपन में वह अपने माता-पिता के साथ खेतों में काम करते थे।

महज पांच-छह वर्ष की उम्र में पेड़ से गिरने के कारण उनके दाहिने हाथ में गंभीर चोट लग गई। समय पर उचित इलाज नहीं मिलने से चोट गैंगरीन में बदल गई और कोहनी के नीचे से उनका हाथ काटना पड़ा।

विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दिलीप ने हार नहीं मानी और पैरा एथलेटिक्स में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने इसी वर्ष इंडिया ओपन और नई दिल्ली ग्रां प्री में स्वर्ण पदक जीते थे। इसके अलावा 2022 एशियाई पैरा खेलों में पुरुषों की 400 मीटर टी47 स्पर्धा का स्वर्ण पदक भी उनके नाम है। ग्लासगो में 100 मीटर टी47 स्पर्धा में दिलीप और मोहम्मद बासिल का शानदार प्रदर्शन भारतीय पैरा एथलेटिक्स के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। दोनों खिलाड़ियों ने एक साथ पोडियम पर स्थान बनाकर भारत का गौरव बढ़ाया और राष्ट्रमंडल खेलों में देश के पदकों की संख्या में महत्वपूर्ण इजाफा किया।

अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास, भावुक संदेश में कहा- हर शुरुआत का एक अंत होता है

नई दिल्ली

भारत के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद टेस्ट बल्लेबाजों में शामिल रहाणे ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक वीडियो संदेश जारी कर अपने 20 वर्षों से अधिक लंबे क्रिकेट सफर को विराम देने का फैसला सुनाया। अपने संदेश में रहाणे ने कहा, ज़िंदगी की सच्चाई यही है कि हर शुरुआत का एक अंत होता है। जब वह समय आता है तो उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बल्लेबाजी में मैंने हमेशा सही टाइमिंग पर भरोसा किया और उसकी अहमियत को समझा।

आज मुझे लगता है कि आगे बढ़ने और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सहित खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का यही सही समय है। उन्होंने कहा, डोंबिवली से एक छोटे लड़के के रूप में अभ्यास करने के लिए सफर करने से लेकर भारत की टोपी पहनने तक, मैंने इस खेल को अपना सब कुछ दिया। हर दिन, हर पारी और बल्लेबाजी का हर मौका मेरे लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने का सपना था। मैंने हमेशा एक सिद्धांत अपनाया कि देश और टीम हमेशा मुझसे ऊपर रहेंगे। मैंने पूरी ईमानदारी से क्रिकेट खेला और हमेशा विश्वास किया कि यदि आपकी नीयत सही हो तो खेल आपका साथ देता है।

रहाणे ने भारतीय क्रिकेट से मिले अनुभवों को याद करते हुए कहा, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद से पिछले 20 वर्षों में भारतीय क्रिकेट ने जबरदस्त प्रगति की है और उसका हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व की बात है। एक भारतीय क्रिकेटर के रूप में मेरा अध्याय भले समाप्त हो रहा हो, लेकिन खेल के साथ मेरी यात्रा खत्म नहीं हुई है। अब मैं अगली पीढ़ी की मदद करना चाहता हूं, उन्हें इस खेल से सीखे गए मूल्य देना चाहता हूं और क्रिकेट को कुछ लौटाना चाहता हूं, जिसने मुझे सब कुछ दिया।

उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई), मुंबई क्रिकेट संघ, अपने साथियों, कोचों, आईपीएल फ्रेंचाइज़ियों, पत्नी राधिका, परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, मेरे करियर में जीत भी मिली और हार भी, गलतियां भी हुईं, लेकिन एक जगह मैं कभी नहीं हारा और वह आप सभी के दिल थे। आपने हमेशा मुझे अपना माना। आपके प्यार, विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद। कैप नंबर 278, अब विदा लेता हूं।

यादगार रहा रहाणे का करियर - अजिंक्य रहाणे का क्रिकेट सफर मुंबई से शुरू हुआ, जहां उन्होंने अपने दूसरे रणजी ट्राफी सत्र में 1,000 से अधिक रन बनाकर राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। उन्होंने 2013 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और जल्द ही डरबन तथा वेलिंगटन में शानदार पारियों से खुद को स्थापित कर लिया। 2014 में लार्ड्स टेस्ट में खेली गई उनकी 103 रन की पारी भारत की 28 वर्षों बाद उस ऐतिहासिक मैदान पर पहली जीत की नींव बनी।

इसके बाद उन्होंने मेलबर्न, कोलंबो और दिल्ली में शतक जड़े तथा विदेशी दौरों पर कई महत्वपूर्ण पारियां खेलीं। वर्ष 2020 के बाक्सिंग डे टेस्ट में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर लगाया गया उनका शतक भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार पारियों में गिना जाता है, जिसने आस्ट्रेलिया में भारत की ऐतिहासिक टेस्ट श्रृंखला जीत की नींव रखी।

2022 में टीम से बाहर होने के बाद रहाणे ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर वापसी की और 2023 की आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल टीम में जगह बनाई। आस्ट्रेलिया के खिलाफ उस फाइनल में उन्होंने पहली पारी में 89 रन बनाकर भारत की ओर से सर्वाधिक स्कोर किया, जो उनका अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच भी साबित हुआ। आईपीएल 2026 में वो केकेआर के कप्तान भी थे।

घातक हो सकता है बैड टी का सेवन

अधिकांश लोग सुबह बिना ब्रश किए बिस्तर पर ही चाय ले लेते हैं। वैसे इसे फैशन का पर्याय माना जाता है किन्तु लोग यह नहीं जानते कि बैड टी हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचाती है। रात को भोजन के दौरान हमारे दांतों में भोजन के कई कण फंस जाते हैं, जो सुबह होने तक सड़ जाते हैं और इससे हमारे मुंह में बहुत बड़ी संख्या में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं।

यदि हम सुबह बिना कुल्ला किए चाय पीते हैं तो ये बैक्टीरिया चाय के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, जो कई रोगों को पैदा करते हैं। रातभर मुंह में एकत्र हुई गंदगी जब सुबह बैड टी के साथ पेट में पहुंचती है तो यह पेट संबंधी कई बीमारियां पैदा करती है।

इससे पेट में घाव हो जाते हैं, जिस कारण व्यक्ति के पेट में तेज दर्द होने के साथ उल्टियां भी आने लगती है। रात के समय पेट में अम्ल बनने की क्रिया अधिक तेज हो जाती है,जो शरीर के लिएहानिकारक है। यह क्रिया छाती में जलन, आमाशय मेंसूजन आदि अनेक बीमारियों को जन्मदेती है।

स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव

धीरे-धीरे एसिडिटी रोग शरीर पर अपना प्रभाव बना लेता है। बेड टी से कब्ज होना आम बात है। कब्ज अपने साथ कई अन्य बीमारियां भी पैदा करती है,जैसे जिगर की खराबी, सिर में दर्द मानसिक परेशानियां व सांसका दुर्गन्धयुक्त होना। खाली पेट चाय पीने से गर्भवती महिलाओं को गर्भपात भी हो सकता है। यह पाचन क्रिया को कमजोर करती है। भूख न लगना, खाने के प्रति अरूचि आदि अनेक समस्याएं बैड टी से ही पैदा होती है। अतः सुबह उठते ही चाय पीने से बेहतर होगा कि आप दो गिलास ताजा पानी पीएं। इससे आपकी कब्ज की शिकायत दूर होकर पेट साफ होगा। बिना कुल्ला किए चाय पीना हर तरह से नुकसानदेह है, इसलिए सदैव ब्रश करने के बाद ही चाय पीएं।

बॉडीबिल्डिंग के लिए आहार

बॉडी बिल्डिंग में मांसपेशियों का आकार बढ़ाया जाता है। बॉडी बिल्डिंग करने वालों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें कार्बोहाइड्रेट भी लेना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो प्रोटीन शरीर को ऊर्जा देने में इस्तेमाल होगा। और इससे उन्हें शरीर बनाने में अधिक वक्त लगेगा। आपको अपने शरीर के वजन के हर किलो के लिए 1.5 से 2 ग्राम तक प्रोटीन लेने की जरूरत होती है।

मलेरिया से बचा सकती हैं मुर्गियां

एक रिसर्च में पता चला है कि मुर्गियां मच्छरों के आतंक से निजात दिला सकती हैं। दरअसल उनसे ऐसी गंध निकलती है जो मच्छरों को दूर रखती है। लोगों को लगता है कि मच्छरों को सिर्फ खून से मतलब होता है, पर ऐसा नहीं है। मच्छरों को भी अच्छे खून और खराब खून में अंतर पता होता है। वे इसे अपनी गंध पहचानने की क्षमता से जान लेते हैं। इसी वजह से मुर्गियां मच्छरों को दूर करने में मददगार होती हैं।

साइटोमेग्लो वायरस से बच्चों में हो सकता है अंधापन

साइटोमेग्लो वायरस महिला, पुरुष या बच्चे को किसी भी उम्र में संक्रमित कर सकता है। इसके ज्यादातर मामले बच्चों में पाए जाते हैं जिसे कॉन्जिनाइटल साइटोमेग्लो वायरस इंफेक्शन कहते हैं।

यह इंफेक्शन संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। जिसका जरिया ब्लड, यूरिन, शुक्राणु या ब्रेस्ट मिल्क हो सकते हैं। ऐसे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान यह वायरस फैलता है।

इसका इलाज व बचाव

जटिलता समझें

- गर्भावस्था में इस वायरस से प्रभावित होने पर पहले तीन माह में गर्भस्थ शिशु को इसका खतरा ज्यादा रहता है।
- जन्म के बाद इसका पता चलता है। गर्भ में यदि बच्चे के दिमाग, आंख या कान पर यह वायरस असर करे तो उसका शारीरिक विकास नहीं होता।
- जिससे उसमें पीलिया, निमोनिया, त्वचा पर दाने, दौरे आना, लिवर बढ़ने, वजन घटने, सिर का आकार छोटा होने जैसी दिक्कतों की आशंका हो सकती हैं।
- कई बार उम्र के बढ़ने पर इसके लक्षण दिखते हैं। जैसे सुनाई न देना, दिखने में परेशानी या अंधापन व दिमागी कमजोरी आदि।

जानें लक्षण

- यह वायरस रक्त के जरिए शरीर के प्रमुख अंगों को प्रभावित करता है।
- सामान्यतः यह वायरस खुद-ब-खुद 5-7 दिन में खत्म हो जाता है लेकिन एडस, ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन डोनेशन, नवजात या ऐसे व्यक्ति जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उनमें इस वायरस के कारण जटिलताएं बढ़ जाती हैं। उनमें यह रक्त के जरिए शरीर में फैलकर खासकर आंख, दिमाग, फेफड़े और लिवर को नुकसान पहुंचाता है।
- जिस कारण बुखार, डायरिया, सांस लेने में तकलीफ, देखने में परेशानी, फेफड़ों में संक्रमण, रेटिनाइटिस (आंख के रेटिना में सूजन), थकान, गले में सूजन व दर्द और मांसपेशियों में दर्द होने जैसे लक्षण सामने आते हैं।
- वायरस से बचाव ही रोग की आशंका को घटाता है।
- हाइजीन और साफ-सफाई को ध्यान में रखना जरूरी है। साथ ही यदि परिवार में कोई सदस्य इस वायरस से पीड़ित हो तो अन्य को सावधानी बरतनी चाहिए।

एंटीवायरल दवाएं कारगर

आमतौर पर यह बीमारी बच्चों या बड़ों दोनों में कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। लेकिन जिनकी इम्युनिटी कमजोर होती है उनमें वायरस के तेजी से फैलने पर दिमाग, आंख और कान प्रभावित होते हैं। इस वजह से मरीज की हालत गंभीर होने लगती है। इसके लिए एंटीवायरल दवाओं का कोर्स शुरू कर इलाज किया जाता है। इससे वायरस के विकास को रोका जाता है।

साफ-सफाई रखना जरूरी

रात की सर्जरी बढ़ाती है मौत की आशंका

रात में की गई सर्जरी से मौत का खतरा दोगुना हो जाता है। हाल ही में आए अध्ययन के परिणाम के अनुसार दावा किया गया है कि रेग्युलर वर्किंग समय के दौरान किए गए ऑपरेशन या सर्जरी की तुलना में रात में की गई सर्जरी या ऑपरेशन में मौत का खतरा दोगुना हो जाता है। मतलब जिन मरीजों का ऑपरेशन या सर्जरी रात में दिन में या वर्किंग समय में ना होकर रात में किया जाता है उनके मरने की संभावना दोगुनी होती है। यहां तक की देर शाम में भी होने वाली सर्जरी में मॉर्टिलीटी रिस्क का खतरा ज्यादा होता है। इस अध्ययन में पिछले 5 सालों में हुए सारे सर्जरी के आंकड़ों को शामिल किया गया है। अध्ययन में 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के सर्जिकल आंकड़ों को लिया गया है। सबसे पहले इसमें सभी तरह के सर्जीकल इंटरवेंशन को शामिल किया गया है। इस अध्ययन में ऑप्थाल्मिक और लोकल एंथेसेसिया के केस को छोड़कर अन्य सभी तरह के वैक्लिपक और आपातकालीन सर्जिकल केसेस को शामिल किया गया है। जिसमें काम करने के घंटों को तीन ब्लॉक में बांट गया। पहले ब्लॉक में सुबह के 7 बजे से लेकर दिन के 3:29 बजे तक के समय को रखा गया। दूसरे ब्लॉक में शाम के 3:30 से रात के 11:29 बजे तक के समय को रखा गया और अंतिम ब्लॉक में रात 11:30 बजे से लेकर सुबह 7:29 बजे तक के समय को रखा गया।

इन ब्लॉक में शुरू हुए ऑपरेशन के समय पर नर्सों ने नजर रखी कि कब ऑपरेशन शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। इस अध्ययन में 41,716 वैक्लिपक और आपातकालीन सर्जरीज को शामिल की गई। इन मामलों में से 10,480 केस इमरजेंसी के थे जिसमें से 3,445 मामलों की सर्जरी पहले ब्लॉक के समय में, 4,951 मामलों की सर्जरी दूसरे ब्लॉक के समय में और 2,084 मामलों की सर्जरी तीसरे ब्लॉक के समय में की गई।

अध्ययनकर्ताओं ने पाया की दिन की तुलना में रात के समय किए गए ऑपरेशन में मरने की संभावना 2.17 टाइम्स अधिक थी। वहीं लेट इवनिंग में किए गए ऑपरेशन में मौत की संभावना दिन के समय हुए ऑपरेशन की तुलना में 1.43 टाइम्स अधिक थी।

अपनी मर्जी से न करें पेन किलर का इस्तेमाल

दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल अपनी मर्जी से न करें दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल अपनी मर्जी से बिल्कुल न करें योंकि ऐसा करने से इनके अच्छे परिणामों की बजाय सेहत पर बुरा असर होगा। डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों को ऐस्पिरिन कभी नहीं देना चाहिए इससे जानलेवा लीवर फेलियर हो सकता है। बच्चे एवं किशोर जो चिकन पाक्स अथवा लू जैसे लक्षणों से रिकवर हो रहे हों उन्हें कभी एस्पिरिन नहीं देना चाहिए पैरासिटामॉल कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए पश्चिमी देशों में यह नंबर वन सुसाइडल एजेंट बन चुका है। दिल के सभी मरीजों को दर्द निवारक दवाओं के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी होता है। अगर किडनी की समस्या से प्रभावित मरीज ने दर्द निवारक दवाका इस्तेमाल किया तो उसे किडनी फेलियर का खतरा बढ़ सकता है। दर्द निवारक दवाओं का बेहद समझदारी से इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि खतरे के दायरे में आने वाले लोगों के लिए एक टेबलेट भी किडनी फेलियर को बढ़ावा दे सकता है।

अब बच्चे खत्म करेंगे पूरा लंच बॉक्स

अक्सर मदर्स की यही शिकायत होती है कि उनका बच्चा लंच बॉक्स में खाना खत्म करके नहीं आता। इसमें पूरा दोष बच्चे का नहीं है, जरा-सा आपका भी है। इसके लिए बच्चों को हेल्दी खाने की आदत डालनी होगी। अगर आपका बच्चा खाने से जी चुराता है और आप इस बात से भी परेशान रहते हैं कि आखिर उसे कैसे लंच बॉक्स दिया जाए, जिसे वह खत्म भी कर ले और उसे पोषण भी मिले तो कुछ टिप्स फॉलो करें।

बच्चों के लंच बॉक्स में ज्यादातर सूखी चीजें रखनी चाहिए, ताकि उन्हें खाने में आसानी रहे। बच्चों की दिलचस्पी का भी ख्याल रखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि उन का रोज का खाना एक जैसा न हो जाए। किसी दिन रोटी सब्जी दें, तो किसी दिन आटे की नमकीन सेंवई, कभी सब्जी पुलाव दे दिया, तो कभी उत्तपम, इडली या दाल का चीला वगैरह भी लंच बॉक्स में रख सकते हैं।

बच्चों के लंच बॉक्स में मौसम के हिसाब से फल भी रखें। इनमें संतरा, केला, सेब, अनार वगैरह ऐसे फल हैं जो बच्चों को आमतौर पर पसंद आते हैं। खीरा, ककड़ी टमाटर, अंकुरित अनाज या दल वगैरह का सलाद रखना न भूलें। बच्चे को पॉकेट मनी दे कर बाहर कैंटीन से खाना खाने की आदत न डालें। ये भी करें- बच्चे की खुराक में दूध को अहमियत दें। उसमें रोजाना दूध पीने की आदत डालें। बच्चे की पंसद के खाने को नजरअंदाज न करें, पर साथ ही पौष्टिक खाना खाने के लिए भी बढ़ावा दें। बच्चा जब भोजन खत्म कर लेता है, तो उसे प्यार से शाबाश या वैरी गुड जरूर कहें।

इन वजहों से रात में भी करें वर्कआउट

सामान्यतः लोग सुबह ही वर्कआउट करने को तरजीह देते हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। सेहत के लिहाज से यह बेहतर भी है। लेकिन देखा जाए तो इन दिनों समय के अभाव से हर कोई बावस्ता है। ऐसे में वर्कआउट के लिए समय निकालना किसी जद्दोजहद से कम नहीं है। सवाल है ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? ऐसी स्थिति में आप चाहें तो रात के समय को चुन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रात को वर्कआउट कर क्या उतने ही फायदे हासिल हो सकते हैं जितने सुबह करने से हासिल होते हैं? एक अध्ययन के मुताबिक देर रात जगने वालों के लिए रात का समय अनुकूल है। दरअसल इस समय वे पूरे लगन से वर्कआउट करते हैं। वे किसी भी तरह की हड़बड़ी में नहीं होते। अतः वर्कआउट करने में पूरा ध्यान देते हैं। इतना ही नहीं वर्कआउट करते हुए वे अतिरिक्त मेहनत भी करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसके बाद उन्हें आराम करना है। मतलब साफ है कि निश्चित मन से रात को वर्कआउट करने वाले ज्यादा फोकस होते हैं। नतीजतन इसका उनकी सेहत पर गहरा असर देखने को मिलता है।

मोबाइल फोन के साथ सोना खतरनाक

आपकी ये आदत बन सकती है परेशानी

जब भी आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल फोन उठाते हैं और सोशल साइट्स के अलावा कई दूसरी चीजें जैसे एसएमएस, मिस या वॉयस काल चेक करते हैं, लेकिन क्या रात में आईफोन या फिर एंड्रॉयड-स्मार्टफोन अपने पास रखकर सोने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर एक दिन आपको बिना स्मार्टफोन के सोना पड़ जाए तो शायद रातभर आपकी आंखों में नींद न आए। स्मार्टफोन न सिर्फ आपकी रातों की नींद उड़ाता है बल्कि आपकी सेहत का भी नुकसान होता है।

बढ़ती है टॉक्सिन की मात्रा

रात में भी आपका ध्यान फोन की तरफ रहता है, जिससे आप अच्छी तरह नींद नहीं ले पाते। रात में अगर आप अपने फोन को अचानक उठाकर देखते हैं तो आपकी आंखें दिमाग को यह संदेश देती हैं कि शरीर को जागना है, जबकि दिमाग शरीर को सुलाने की कोशिश करता है। आपके दिमाग को रेस्ट करने का समय नहीं मिलता, जिससे शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आप अच्छी तरह नींद नहीं ले पाते। दिन में आप काम पर फोकस कर नहीं पाएंगे, साथ ही शरीर भी सुस्त रहेगा। दिन में 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है। इसलिए अगर रात में आपको मोबाइल चलाने का बहुत शौक है तो आप अपने इस शौक को जरा विराम लगाई। वरना एक अच्छी सेहत आप खो देंगे।

बढ़ने लगता है आपका वजन

दिन-ब-दिन आपकी काबिलियत कम होती जाएगी, इसका सीधा कारण है नींद न पूरी होना, साथ ही आपका वजन भी बढ़ने लगेगा। कम सोने से शरीर के मैटाबॉलिज्म में बदलाव होने लगता है, जिससे शरीर का भार बढ़ता है। ज्यादातर डॉक्टरों का इस बारे में यही कहना है 9.00 बजे के बाद अपने फोन को खुद से दूर रखें और अपने शरीर की घड़ी के अनुसार चलें। यानि जब सोने का समय हो तो शरीर को सोने दें। वरना इस तरह की आदत से आप कई बीमारियों को आमंत्रित कर लेंगे। सोते समय मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखने में ही समझादी है। और इससे आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं।

रेसिपी

मखमली पनीर टिक्का

सामग्री

200 ग्राम पनीर(कटा हुआ)
1/2 कप दही
1/4 चीज(कद्दूकस किया)
1/2 छोटा चम्मच हरी मिर्च(पेस्ट)
1 टेबलस्पून काजू पाऊडर
1/2 छोटा चम्मच गर्म मसाला
1 टीस्पून काली मिर्च पाऊडर
नमक स्वादानुसार

विधि

सबसे पहले एक बर्तन में दही लेकर इसमें हरी मिर्च,काजू पाऊडर, गर्म मसाला,काली मिर्च,नमक और चीज डालकर मिक्स करें। अब इसमें पनीर के टुकडे लपेट कर 15-20 मिनट के लिए रख दें। माइक्रोवेव को 200 डिग्री पर प्रीहीट कर लें और फिर पनीर के टुकड़ों को स्टिक पर लगा कर माइक्रोवेव में 15 मिनट तक ग्रिल करें। आपका मखमली पनीर टिक्का बनकर तैयार है। इसे सॉस के साथ सर्व करें।

शिमला मिर्च की लौंजी

सामग्री

1 कप शिमला मिर्च के टुकड़े, 2 टेबल-स्पून तेल ,1/2 टी-स्पून कलौंजी, 1 टी-स्पून सौंफ
1 टी-स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक चुटकी हल्दी पाउडर, 2 टी-स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टी-स्पून लाल मिर्च पाउडर, 3/4 टी-स्पून अमचुर
2 टेबल-स्पून शक्कर, नमक स्वादअनुसार

विधि

एक चौड़े नॉन-स्टिक पैन में तेल गरम करें, कलौंजी, सौंफ और हरी मिर्च डालकर मध्यम आंच पर 1 मिनट के लिए भून लें। शिमला मिर्च डालकर कुछ और सेकेन्ड तक मध्यम आंच पर भून लें। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अमचुर डालकर अच्छी तरह मिला लें और मध्यम आंच पर 1 मिनट के लिए पका लें। 1/2 कप पानी, शक्कर और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें और मध्यम आंच पर 4-5 मिनट या शिमला मिर्च के नरम होने तक, बीच-बीच मे हिलाते हुए पका लें। तुरंत परोसें या हवा बद डब्बे में डालकर 2-3 दिनों के लिए फ्रिज में रखें।

कहीं आप भी 'फोमो' के शिकार तो नहीं

अगर आप फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि आप 'फोमो' यानि 'फीयर ऑफ मिसिंग आउट' के शिकार हों। स्मार्टफोन के जरिए अपने दोस्तों और हर पल होने वाली बातों के टच में रहने की लगातार इच्छा आपको 'फोमो' का शिकार बना सकती है।

क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट रीपेन सिप्पी की मानें तो जिन लोगों को सोशल मीडिया की आदत हो चुकी है, इससे दूर रहने पर वे 'फोमो' का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग जब ज्यादा देर तक सोशल मीडिया से दूर रहते हैं तो उन्हें बेचैनी-सी महसूस होती है। वहीं कंसल्टेंट क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट आशिमा श्रीवास्तव का कहना है कि 'फोमो' सोशल एंजाइटी का रूप है ।

जब नहीं मिलता अटेंशन

बहुत सारे लोग जिन्हें रीयल लाइफ में प्यार और अटैंशन नहीं मिलता वे इन चीजों को वर्चुअल वर्ल्ड में ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब उन्हें वर्चुअल वर्ल्ड में ये सब कुछ मिलता रहता है, वे खुश रहते हैं पर जिस पल उन्हें अटैंशन मिलना बंद हो जाता है, 'फोमो' फोबिया उन पर हावी हो जाता है। ऐसे में आपके मन में 'फीयर ऑफ मिसिंग आऊट' जैसी बातें आने लगती हैं।

रिश्तों पर बुरा असर

लोगों को वर्चुअल वर्ल्ड में जीने की इतनी आदत हो जाती है कि वे रीयल लाइफ सिचुएशंस को फेस ही नहीं कर पाते। यही बातें दूसरों के साथ उनके रिश्तों में भी असंतुलन पैदा कर देती हैं और रीयल लाइफ की किसी परिस्थिति में वे जल्दी प्रतिक्रिया ही नहीं दे पाते। ऐसे में दोस्तों और परजिनों के साथ उनके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं।

आपके भीतर पैदा कर देता है 'डर'

'फोमो' में एक व्यक्ति के भीतर डर विकिसत होने लगता है कि वह जरूरी अपडेट्स और महत्वपूर्ण इवेंट्स को मिस कर देगा। इसी डर की वजह से वह लगातार अपने मोबाइल फोन को चेक करता रहता है। सामान्यतः कोई व्यक्ति 'फोमो' के शिकंजे में तब आता है, जब वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद को उपेक्षति या अकेला महसूस करने लगता है ।

सोशल बिहेवियर पर असर

मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि सिर्फ 'फोमो' ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज्यादा इस्तेमाल से सोशल बिहैवियर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे वयस्कों, युवाओं और यहां तक कि स्कूल जाने वाले बच्चों के वर्क परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है । वे अंतर्मुखी होने लगता है और सामान्यतः लोगों को खुश करने वाली बातों से भी उसे खुशी नहीं होती।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**